

आपके पास खाली समय है, किसी सीनियर से कानून सीखकर आओ; SC ने वकील को लताड़ा

नई दिल्ली। एक वेतुकी याचिका दाखिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वकील और याचिकाकर्ता, दोनों को लताड़ा लगाई। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता-वकील को 'कुछ कानून' सीखने की सलाह दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित



याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत के सभी आदेशों का पालन करना होता है। पीठ ने कहा, "न्यायालय के आदेश से शासित होने वाले सभी पक्ष इसका पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो अपील आदि पर निर्भर करता है। रिट याचिका नहीं दायर की जा सकती।" पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। न्यायालय ने आश्चर्य जताते हुए कहा, "किसी रिट याचिका पर विचार करते हुए एक सामान्य आदेश कैसे पारित किया जा सकता है?" पीठ ने तमिलनाडु के मद्रुरै निवासी याचिकाकर्ता-वकील केके रमेश को वरिष्ठ अधिवक्ता से कुछ कानून सीखने की सलाह दी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "आपके पास कुछ खाली समय है। मुझे लगता है कि आप किसी वरिष्ठ के साथ जुड़ सकते हैं और कुछ कानून सीख सकते हैं। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि ऐसी याचिकाएं दायर न करें। न्यायालय के आदेशों का पालन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। अनुपालन नहीं होने पर निर्देश दिये जाते हैं। कानून यह है कि आपको पारित किये गए आदेशों का पालन करना होगा।"

डबल मुसीबत में हेमंत सोरेन, कल्पना को सीएम बनाया तो परिवार में ही बगावत का डर; भाभी के बागी सुर

रांची। इंडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में सियासी सर्गामी एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद झामुमो, कांग्रेस और राजद विधायकों की बैठकों के कई दौर चले। राज्य में विपरीत परिस्थिति होते ही और मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ने पर झारखंड के नेतृत्वकर्ता का चेहरा बदल सकता है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकता है। वे झामुमो विधायक दल की नेता बन सकती हैं और राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। मंगलवार देर रात तक चली महागठबंधन विधायकों की बैठक में इस पर सहमति भी बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए अधिकृत किया गया है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री किसी को भी सीएम का उम्मीदवार बनाते हैं तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है और वे उनके फैसले के साथ रहेगी। वहीं, अगर कल्पना सोरेन का नाम आने पर झामुमो और परिवार में विरोध होता है तो झामुमो कोटे के मंत्री चंचई सोरेन और मंत्री जोबा मांझी का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे लाया जा सकता है। इन नामों पर सोरेन परिवार के साथ पार्टी के अन्य विधायकों में भी विरोध होने की संभावना



नहीं है। वहीं, कल्पना सोरेन के नाम पर सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और भाई बसंत सोरेन विरोध करते हैं और भाजपा की ओर जाते हैं तो पार्टी को टूटने से बचाने का भी संकट सामने होगा। हालांकि, झामुमो की मानें तो इस तरह की चर्चा का

वहीं, अगर पार्टी के दो तिहाई विधायक इनके साथ होंगे तो वे पार्टी से अलग हो सकते हैं। वैसे इसकी संभावना कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इसके उदाहरण हैं।

सीता ने कहा, अपनी भतीजी को क्यों नहीं आशीर्वाद देते

वे झामुमो विधायक दल की नेता बन सकती हैं और राजभवन जाकर राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। मंगलवार देर रात तक चली महागठबंधन विधायकों की बैठक में इस पर सहमति भी बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए अधिकृत किया गया है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री किसी को भी सीएम का उम्मीदवार बनाते हैं तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है और वे उनके फैसले के साथ रहेगी।

विपरीत परिस्थिति आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को सीएम बनाने की चर्चा पर उनकी भाभी और प्रयास से झामुमो विधायक सीता सोरेन नाराज बताई जाती हैं। वह मंगलवार को विधायक दल

की बैठक में नहीं आईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीता सोरेन ने कहा है कि कल्पना सोरेन उन्हें किसी हाल में स्वीकार नहीं हैं। उनके दिवंगत पति दुर्गा उरांव ने झामुमो के स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया है। उम्मीद होने पर अब वह चुप नहीं रहेंगी। दो बच्चियों को उन्होंने काफी तकलीफ से पाला है। घर की बड़ी बहू होने के नाते उनका हक बनता है। उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं। अगर हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पुत्री से ब्रेक हो तो वे पिता के तौर पर उसे आशीर्वाद दें।

हेमंत लामबंदी में जुटे, कहा- लड़कर जीतेंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडी की कार्रवाई के खिलाफ लामबंदी में जुट गए हैं। उन्होंने दिल्ली से रांची लौटते ही सत्ताधारी गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों के साथ अपने आवासिय कार्यालय में मंगलवार दोपहर दो बजे बैठक की। उन्होंने सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया। बैठक के बाद सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे। बापू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमंत ने लापता होने के सवाल पर कहा ऐसी बात क्यों, मैं तो यहीं हूँ। उन्होंने यह भी कहा- लड़े हैं, लड़ेंगे, जीते हैं, जीतेंगे।

नीतीश कुमार के पाला बदलने से भाजपा को कितना फायदा? प्रशांत किशोर ने बताया

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हालांकि, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को क्या फायदा होगा इस विषय पर चर्चा हो रही है। चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को वापस लेकर युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारने वाली रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार का विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने दम पर वह ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे जिससे कि पाला पलट जा सके। लेकिन अवधारणा के लिहाज से यह इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है। भाजपा उन्हें एनडीए में वापस लेकर युद्ध जीतने के लिए लड़ाई हारने की रणनीति अपना रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें



कल्पनाकारों में से एक को बाहर कर भाजपा को मनेवैज्ञानिक झटका दिया है। उन्होंने कहा, यह बीजेपी के लिए उतना बड़ा लाभ नहीं है, बल्कि विपक्ष के लिए एक मनेवैज्ञानिक झटका है। बीजेपी किसी भी तरह से काफी आगे चल रही है। नीतीश के पाला बदलने के साथ ही बीजेपी ने विपक्ष को एक मनेवैज्ञानिक झटका दिया है। प्रशांत

किशोर ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन इससे काफी पहले हो सकता था। चुनाव रणनीतिकार ने कहा, विपक्षी दल जानते थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में ही होंगे। अगर उन्होंने 2022 या 2021 में गठबंधन बनाया होता तो उनके पास चीजों को सुलझाने के लिए दो साल होते। आपको बता दें कि नीतीश कुमार द्वारा रिक्त नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन छोड़ने के लिए जद (यू) प्रयुक्त की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। इसलिए वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इंडिया अलायंस में ममता-अधीर के बीच फिर खिंची तलवार

सीएम ने तेज किए हमले

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस में साथी दलों के बीच चौड़ी होती खाई को फिर उजागर किया है। मंगलवार को राज्य के उत्तरी हिस्से में पदयात्रा करते हुए ममता ने लोगों से तुणमूल कांग्रेस के बैनर तले एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-लेफ्ट और बीजेपी को हारने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के जिन शहरों से होकर गुजरे, उन्हीं शहरों चोपड़ा और इस्लामपुर में कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा वह तुणमूल कांग्रेस ही है, जो राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। हमें बंगाल में कांग्रेस-सीपीआई (एम)-बीजेपी गठजोड़ को हारने के लिए एकजुट होना चाहिए। ममता की यह टिप्पणी उस दिन आई जब पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने तुणमूल पर बंगाल में पदयात्रा के रास्ते में बाधाएं



पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहेंगे। चौधरी ने मुर्शिदाबाद में मीडियाकर्मियों से कहा, अगर पश्चिम बंगाल में चोरी हो रही है, तो क्या मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं हो रहा है?...क्या हम भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को भ्रष्ट नहीं कह सकते। चौधरी ने कहा, अनीश खान (खवड़ा में एक युवक) को हत्या के लिए किसी को अब तक रिपारत नहीं किया जा सका है। लगता है इस मामले में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। स्कूली शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली तो लोग कोर्ट चले गये राशन

नहीं मिलने (राशन घोटाला) के मामले में भी लोग कोर्ट आए। अब अदालत सीबीआई और इंडी से जांच के आदेश दे रही है। बता दें कि तुणमूल कांग्रेस लंबे समय से अधीर रंजन चौधरी पर दोनों पार्टियों के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने का आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी इस समय उत्तरी पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक दौरे पर हैं। उन्होंने उल्लेख उत्तर दिनांक के चोपड़ा शहर में जोनी संजोय यात्रा निकाली। इसके बाद उन्होंने पास के इस्लामपुर में भी एक और पदयात्रा की। चोपड़ा शहर से गुजरे हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क के किनारे खड़े लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं, महिलाओं और बच्चों सहित स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। जब यात्रा विभिन्न इलाकों से गुजर रही थी, तब कई लोगों को दीदी...दीदी के नारे लगाते हुए देखा गया। कई लोगों ने फूल बरसाए और कुछ ने शंख बजाया। ममता बनर्जी ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। तुणमूल

सड़क बनाने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश, 26 हफ्ते की छुट्टी

नहीं कटेगा कोई वेतन

नई दिल्ली। सरकार ने नियोजताओं से कहा है कि सड़क निर्माण करने वाली पंजीकृत महिला कर्मियों को दो प्रसूतियों के लिए 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जाए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि दो बच्चों के बाद की प्रसूति के लिए नियोजता को 12 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देना होगा। केंद्रीय मंत्री इरानी ने मंगलवार को यह घोषणा तब की जब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश

श्रम मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त एडवाइजरी में कहा कि देश भर में महिला कर्मियों को 26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्रविधान किसी क्रांति से कम नहीं है। इरानी ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों को केवल कागज पर जारी नहीं किया गया, बल्कि अफसरों को महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। अगर

किसी गर्भवती कर्मचारी का गर्भपात होने की स्थिति में उसे इस हदसे के दिन से ही मातृत्व अवकाश की सुविधाओं के साथ छह हफ्ते का अवकाश मिलेगा।

जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी

इरानी ने कहा कि एडवाइजरी के अनुसार महिला कर्मचारियों को आनलाइन भुगतान सुनिश्चित करना होगा ताकि उनका सुपरवाइजर उनके वेतन में कटौती न कर सके। महिलाओं को कार्यबल में बढ़ावा देने के लिए रात्रि पाली और आवागमन के लिए जरूरी सुविधाएं देनी होंगी।

क्रेच के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार छह महीने और उससे बड़े बच्चों के लिए क्रेच के लिए राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम मानक और प्रोटोकाल जारी किए गए हैं। इसके तहत कार्यालयों, आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों आदि स्थानों पर घंटे, हफ्ते या महीने के शुल्क पर यह सुविधा दी जाए।

राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर है चुनाव, क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपनी एक सीट?

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या का असर राज्य सभा चुनाव में दिखेगा। यह अगले पांच सालों तक रहेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 70 सीट मिली है। 2018 की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या करीब 33 कम हुई है। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सीटों पर वोटिंग होगी। दो सीट बीजेपी के पास हैं। जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है। तीन सीटों में से 2 पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस काबिज है। अभी के गणित के हिसाब से राजस्थान में एक सीट पर जीत के लिए 58



वोटों की जरूरत होती है। अभी सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में दो सीटें पक्की हैं। कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है।

चुनाव बाद बदल गया है पूरा गणित दरअसल, राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है।

बीजेपी के पास खुद के 115 विधायक हैं। जबकि करीब एक दर्जन निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को मिला हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि दो सीटों पर आसानी सी जीत हासिल कर लेंगी। हालांकि, तीसरी सीट के लिए बीजेपी को करीब 16 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जोड़ तोड़ में माहिर बीजेपी की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में दो सीटें पक्की हैं। कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है।

27 फरवरी को मतदान होगा

राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

की सीटों पर वोटिंग होगी। राज्यसभा की इन तीनों सीटों पर इस साल तीन अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सवाइ माथोपुर से जीत दर्ज की थी। वहीं विधायक बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब इस पर मतदान होने जा रहा है।

चुनाव आयोग के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर आठ फरवरी को नॉटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 15 फरवरी को नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 16 फरवरी को नामांकन स्वरूपाई होगी। वहीं 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा और 27 फरवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। 27 फरवरी को ही शाम पांच बजे मतगणना होगी।

दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, कोहरे-शीतलहर ने तोड़ा 21 सालों का रिकॉर्ड; 13 साल बाद दिन-रात इतने ठंडे

नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। जनवरी के ज्यादातर दिन बहुत सर्द और घने कोहरे वाले रहे। धूप के दर्शन भी कम ही हुए। इन सभी कारणों की वजह से दिल्ली में जनवरी का महीना 21 साल बाद सबसे ठंडा रहा। सफदरजंग वेराशाला के अनुसार, महीने का अधिकतम औसत तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस था, जो 2015 के समान और 2003 के बाद सबसे कम था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, 33 साल पहले के रिकॉर्ड में केवल तीसरी बार है जब जनवरी में अधिकतम औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अन्य दो साल 2015 और 2003 थे, जब औसत तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जनवरी

में अधिकतम सामान्य तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस है, जो इस महीने दर्ज किए गए तापमान से 2.2 डिग्री अधिक है। जनवरी 2024 में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही, घने कोहरे वाली सुबह और हाड़ कंपाने वाली ठंड ने इस महीने को 2003 के बाद से दिन के समय या अधिकतम तापमान के मामले में सबसे ठंडा बना दिया। जनवरी में दिन का औसत तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम दर्ज किया गया था। 2015 में भी इतना ही अधिकतम औसत तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि, 2003 में अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस था। राजधानी में 13 साल, 2013 के बाद जनवरी में रात और दिन दोनों ही सामान्य से



ज्यादा सर्द रहे। इस महीने का औसत न्यूनतम तापमान 6.43 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही पांच दिन शीत लहर और पांच दिन शीत दिवस की स्थिति रही। पहले के वर्षों में आमतौर पर किसी

एक स्थिति का ही प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता रहा है। दिल्ली में इस बार जनवरी में सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ रही है। परेशानी की बात यह है कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान सामान्य से कम हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री कम होने पर उसे शीतलहर की स्थिति कहा जाता है। इस बार जनवरी में ऐसे पांच दिन रहे हैं। न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री कम होने पर उसे शीत दिवस कहते हैं। इस पांच दिन शीत दिवस रहे। इसका मतलब यह है कि शहर में कम से कम एक दशक में जनवरी में सबसे अधिक चरम मौसम वाले दिन देखे गए। ठंड के साथ-साथ दिल्ली में अधिकतर दिनों में घने कोहरे की चादर छाई रही।

आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 32 सालों में, जनवरी में औसत अधिकतम तापमान केवल तीन बार 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया। जनवरी 2024 और 2015 दोनों में औसत अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जनवरी 2003 की तुलना में केवल 0.3 डिग्री अधिक है।

इस बार रिकॉर्ड टूटा

● इस बार जनवरी में पांच दिन शीतलहर और पांच दिन शीत दिवस के रहे
● 2023 में आठ दिन शीत दिवस वाले थे और शीत लहर केवल एक दिन ही रही थी
● वर्ष 2022 में शीत लहर वाले सात दिन थे, जबकि शीत दिवस की स्थिति एक दिन भी नहीं बनी

संपादकीय

इंडी से बचने के लिए

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रवर्तन निदेशालय, यानी इंडी के अधिकारियों के बीच सोमवार और मंगलवार को जो लुकाछिपी का खेल चला, वह चिंताजनक तो है ही, साथ ही काफी दिलचस्प भी है। इंडी जमीन घोटाले के बारे में काफी समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हर बार जब समन जारी होता है, वह नहीं पहुंचते। रविवार को वह सरकारी विमान से नई दिल्ली पहुंचे, तो सोमवार देर रात इंडी ने उनके दिल्ली स्थित निवास-स्थान पर छापे मारा। इंडी ने दावा किया कि उसे छापे में कुछ कागजात, 36 लाख रुपये नकद और एक एसयूवी कार मिली। मगर हेमंत सोरेन नहीं मिले। जब संपर्क की कोशिश की गई, तो मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के फोन बंद मिले। मंगलवार को यह खबर मीडिया के जरिये लोगों तक पहुंची ही थी कि पता चला कि मुख्यमंत्री रांची के अपने सरकारी निवास-स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उन्होंने इंडी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह पूछताछ के लिए बुधवार को दोपहर एक बजे अपने निवास पर उपलब्ध रहेंगे। इंडी अधिकारी वहां उनसे पूछताछ कर सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से यह कहा जा रहा है कि झारखंड जमीन घोटाले को लेकर इंडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अगर यह सिर्फ आशंका है, तब भी एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह आने वाले राजनीतिक संकट को देखते हुए प्रदेश को कोई व्यवस्था देने की कोशिश करेगा। मगर हेमंत सोरेन इससे भी बचने की कोशिश करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वरिष्ठ राजनेता और मुख्यमंत्री यह कैसे सोच लेता है कि वह इंडी जैसी एजेंसी की पूछताछ से हमेशा के लिए बच सकता है? वैसे, ऐसा करने वाले हेमंत सोरेन अकेले नहीं हैं। यही काम कुछ अन्य राज्यों के नेता और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अगर हम हेमंत सोरेन के आरोप को सही मान भी लें कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, तो एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ की तरह उनसे उम्मीद की जाती है कि वह इन कोशिशों का राजनीतिक मुकाबला करेंगे। जबकि, भागने की कोशिशों से तो उनकी राजनीतिक छवि ही खराब होगी, और बहुत से लोग यह मानने पर बाध्य होंगे कि दाल में कुछ काला है। हेमंत सोरेन अगर चाहे, तो अपने पड़ोसी राज्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी यादव से इस मामले में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी दौरान पटना में पूरे एक दिन इंडी ने 75 वर्षीय लालू यादव से पूछताछ की। अगले दिन तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो गई। इंडी के खिलाफ उनके आरोप भी वहीं हैं, जो हेमंत सोरेन के हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इससे बचा नहीं जा सकता और इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से ही लड़ना होगा। हालांकि, इंडी भी पिछले कई साल से विवादों में रही है। खासकर राजनीतिज्ञों के खिलाफ जांच करने और फिर उनमें से कुछ को वलीन व्हीट दे देने के मामले में इंडी के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप भी सामने आते रहे हैं। पिछले दिनों आए आंकड़े बताते हैं कि इंडी ने अब तक जितने भी लोगों पर आरोप लगाए हैं, उनमें आरोप-सिद्धी की दर 0.5 फीसदी ही रही है। मगर इस सबका अर्थ यह नहीं है कि इंडी जब समन जारी करे, तो नेता भागते फिरें। लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि कैंस भी संकट आए, उनके नेता पूरी मर्यादा के साथ चुनौती का मुकाबला करने का उदाहरण पेश करेंगे।

आज का राशीफल

| | |
|----------------|--|
| मेष | संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक समस्याएँ रहेंगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। जीविका की दिशा में प्रगति होगी। रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। |
| वृषभ | पारिवारिक जनों के साथ सुखद समाचार मिलेगा। जारी प्रयास सफल होंगे। खानपान में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। |
| मिथुन | व्यावसायिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशांतर की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। |
| कर्क | बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपये पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। जीवन साथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। |
| सिंह | पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दिशा में प्रगति होगी। वाणी की सौम्यता प्रतिष्ठा में वृद्धि करायेंगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। धन लाभ के योग हैं। |
| कन्या | जीवन साथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक दिशा में चल रहा प्रयास सफल होगा। |
| तुला | पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वाणी की सौम्यता व्यर्थ के विवादों से आपको बचा सकती है। स्वास्थ्य शिथिल रहने की संभावना है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुभव प्राप्त होंगे। |
| वृश्चिक | दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। |
| धनु | व्यावसायिक योजना सफल होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्यशु कष्ट ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। यात्रा देशांतर की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। |
| मकर | बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। |
| कुम्भ | पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। |
| मीन | जीवन साथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलायेगी। |

विचारमंथन

(लेखक - सनत जैन)

भ्रष्टाचार के आरोप अब राजनीति के सबसे बड़े अस्त्र साबित हो रहे हैं। पिछले चार दशक में राजनीति का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। आरोप लगाओ, उस पर राजनीति करो, राजनीति के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचो। आरोप झूठे हो या सच्चे हों, सजा हो या ना हो, लेकिन आरोपों की राजनीति में सत्ता का सिंहासन मिल जाता है। तो फिर इसको राजनीति के रूप में इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने वह बोफोर्स तोप में दलाली का आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर लगाया था। वह राजीव गांधी

मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे उनके द्वारा लगाए गए आरोप को काफी गंभीरता से लिया गया। भारतीय राजनीति में इसका बड़ा असर हुआ 1989 का लोकसभा चुनाव इसी बोफोर्स के आरोप में राजीव गांधी चुनाव हार गए। केंद्र में गठबंधन की दूसरी बार सरकार बनी। जिसमें कई राजनीतिक दल शामिल थे। विश्वास प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बोफोर्स के आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए। 1989 के बाद से लगातार गठबंधन की सरकार कई बार की संसदीय सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बोफोर्स घोटाले का सच आज तक सामने नहीं आया। हां जांच के नाम पर अरबों रुपये जरूर सरकार के खजाने

से खर्च हो गए। बोफोर्स तोप की दलाली में आज तक गांधी परिवार को दोषी नहीं ठहराया जा सका। लेकिन आरोप आज भी गांधी परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 2011 के बाद से एक बार फिर आरोपों की राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्र में जब तत्कालीन मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल के लोकलाफ ऑडिट में कई ऐसी मनगढ़ंत आरोप लगाए। जिन पर जांच भी हुई, उसके बाद भी उस पर किसी को सजा नहीं हुई। 2 जी टेलीकॉम घोटाला और कोयला घोटाला बड़ा चर्चित हुआ। लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि काल्पनिक आरोप

लगाए गए थे। मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे आरोप लगाए गए जो आज तक साबित नहीं हो पाए हैं। लेकिन राजनीति में अभी भी कांग्रेस और उसके नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने के लिए उन्हीं आरोपों का बार-बार प्रयोग किया जाता है। 2014 के बाद से देश में जो राजनीति चल रही है। उसमें आरोपों को आधार बनाकर सीबाआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां लगातार जांच करती हैं। पिछले 10 वर्षों में किसी भी आरोप में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा तथा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार को बेचने के नाम पर आर्थिक

घोटाले की जांच पिछले कई वर्षों से की जा रही है। लेकिन इनकी जांच ही चल रही है। कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। वर्तमान कानून के हिसाब से उन्हें दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। अतः जांच के नाम पर कई वर्षों तक मामले को लटकाए रखना और चार्ज शीट पेश न करना राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है। चारा घोटाले में कई वर्षों तक लालू यादव जेल में रह चुके हैं। डेढ़ दशक पहले के मामले को पुनः जांच में लेकर रावडी देवी, मीशा यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं सभी विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री और जो प्रमुख राजनेता हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इंडी और सीबीआई जांच शुरू कर दी है। कहा जाता है कि जो भाजपा में नहीं आता है, उनकी गिरफ्तारी इंडी कर लेती है। जमानत पर उन्हें दामिनी बना दिया जाता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन एवं मनीष सिंसोदिया को शराब घोटाले में कई महीनों से जेल में बंद करके रखा गया है। कोर्ट में चार्ज शीट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। कई महीनों तक नेता जेल में बंद रहते हैं। केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और अब मीडिया आरोपों को लेकर एक माहौल बनाता है। भारत के सभी विपक्षी दल इस

समय भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं, यह छवि विपक्षी नेताओं की बना दी गई है। सबसे बड़े आक्षेप की बात यह है, कि किसी भी मामले में चार्ज शीट पेश नहीं की जाती। बिना जांच के भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। विशेष कानून के तहत इसकी जांच शुरू हो जाती है। जांच और गिरफ्तारी के नाम पर जो राजनीति हो रही है। उसने भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही बदल दिया है। न्यायपालिका में भी आरोपों के आधार पर जो राजनीति हो रही है। कई महीनों तक जेल में बंद रखने के बाद भी, जब जांच एजेंसियां सबूत भी पेश नहीं कर पाती हैं। उस समय न्यायपालिका का मौन यह साबित करता है।

आकर्षक पैकेज में रोगवर्धक प्रोसेस्ड फूड

विश्वनाथ सचदेव

आधी सदी से कुछ ज्यादा ही पुरानी बात है। हरियाणा के पलवल चुनाव क्षेत्र से 1967 में गया लाल नामक उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के तत्काल बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर एक दिन के भीतर-भीतर उन्होंने तीन बार पाला बदला-कांग्रेस से जनता पार्टी में, फिर वापस कांग्रेस में और फिर जनता पार्टी में। इसी 'खेल' में जब उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के समक्ष पेश किया गया तो सम्बन्धित नेता ने कहा था 'गया राम अब आया राम हो गये हैं'। तभी से दल बदलुओं के लिए एक मुहावरा बन गया। आज जिस संदर्भ में यह चर्चित किस्सा याद आ रहा है, उसका सम्बंध 'दल बदल' से तो नहीं, पर 'सरकार-बदल' से जरूर है। और इस प्रक्रिया में गया राम को पलदूराम की संज्ञा दी गयी है। बिहार की महागठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। डेढ़ साल पहले ही वे अपने दल जदयू के साथी दल भाजपा का दामन छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिले थे, मिलकर सरकार बनायी थी। तब उन्होंने कसम खायी थी कि मर जाऊंगा पर भाजपा के साथ फिर नहीं जाऊंगा। उस कसम का क्या हुआ, वही जानें, पर नीतीश कुमार आज फिर यह कह कर भाजपा के साथ हो गये हैं कि 'अब इधर-उधर नहीं जाना है'। इधर-उधर से उनका क्या मतलब है, यह बात समझना भी आसान नहीं है। उनका इतिहास बताता है कि वे कब पलटी खा जाएं, पता नहीं। हां, अब इतना सबको पता है कि 'गया राम' की तरह ही 'पलदूर राम' भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया है। भारत का जागरूक नागरिक इन पलदूर रामों से पूछ रहा है- 'यह बता कि काफिला क्यों लुटा?' और यदि नहीं पूछ रहा है तो उसे पूछना चाहिए यह सवाल। विडम्बना यह भी है कि हमारे नेता, चाहे वे किसी भी रंग के क्यों न हों, इधर-उधर की बात करके मतदाता को भरमाने में महारत हासिल कर चुके हैं। झूटे

वादे और दावे उनके लिए किसी भी प्रकार की शर्म का कारण नहीं बनते। मतदाता को भले ही कभी इस बात पर शर्म आ जाये कि उसने दल बदलू या पलदूराम का समर्थन क्यों किया था, पर हमारा नेता इस बात की कोई आवश्यकता नहीं समझता कि वह अपने मतदाता को बताये कि उसने जो कुछ किया है, वह क्यों किया है। विडम्बना यह भी है कि हमारी राजनीति में राजनीतिक शुचिता के लिए शायद ही कहीं कोई स्थान बचा है। जनतंत्र एक ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घोषित नीतियों और दावों-वादों के अनुरूप कार्य करेगा। हां, चुनावों से पहले ऐसा करने की घोषणाएं जरूर की जाती हैं, पर फिर बड़ी आसानी से उन्हें भुला दिया जाता है। मान लिया जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है! जनतंत्र का तकाजा है कि जनता अपनी याद दाश्त मजबूत बनाये रखे। तभी जनतंत्र सफल हो सकता है, और सार्थक भी। 'जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा' जो सरकार बनती है, उसकी सफलता-सार्थकता का आधार यही है कि जनता अनवरत सजग रहे- न केवल अपने नेताओं की कथनी-करनी को लेकर, बल्कि अपने अधिकारों-दायित्वों के प्रति भी। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या हमें किसी 'गयाराम' या 'पलदूराम' से उसके किये-करे की कैफियत नहीं पूछनी चाहिए? जनतंत्र में राजनीति के खिलाड़ी अपनी घोषित-नीतियों, वादों और दावों के आधार पर चुनाव जीतते-हारते हैं। भले ही हमेशा ऐसा हो नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि चुनाव नीतियों के आधार पर ही होते हैं। माना यह भी जाता है कि चुनाव जीतने वाला इन नीतियों के अनुसार अपना आचरण रखेगा। अपनी घोषित नीतियों पर टिका रहेगा। पर ऐसा अवसर होता नहीं। अवसर राजनेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनतंत्र की मूल भावना के साथ छल करते दिखाई देते हैं। दल-बदलुओं का आचरण इसी का उदाहरण है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को राजनीति की विवशता कहना-मानना वस्तुतः जनता के साथ विश्वासघात ही है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही होता है। लेकिन यह



कहकर कि दुनिया के अन्य कई जनतांत्रिक देशों में भी यह 'बीमारी' है, हम अपनी बीमारी की गम्भीरता को कम नहीं आंक सकते। इसीलिए हमने लगभग चालीस साल पहले दल-बदल कानून की आवश्यकता को समझा था और 52वें संशोधन के तहत यह कानून बनाया गया था। फिर सन् 2003 में 91वें संशोधन के तहत इस कानून को कुछ और ताकतवर बनाया गया। पर बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया। लेकिन इलाज तो करना होगा। लेकिन कैसे? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। लेकिन जनतंत्र की सफलता का तकाजा है कि इलाज की कोशिशें जारी रहें। यह अपने आप में एक विडम्बना ही है कि ऐसी कोशिशों के तहत जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष ने दलबदल-विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति गठित करने की घोषणा की, उसी दिन बिहार के 'सुशासन बाबू' ने अपनी गठबंधन की सरकार का त्यागपत्र देकर भाजपा का दामन थाम लिया और वहां नयी सरकार बन गयी। न नीतीश कुमार को इस बात की कोई चिंता थी कि इससे उनकी छवि खराब होगी और न ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली

भाजपा ने यह सोचा कि नीतीश कुमार को फिर से अपने साथ लेकर वह एक अनैतिक काम कर रही है! हकीकत तो यह है कि अब हमारी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है। सता ही हमारी राजनीति के केंद्र में है। गांधी ने सेवा के लिए राजनीति की बात कही थी। अब न उस बात को सुना जा रहा है, न याद रखने की कोई आवश्यकता महसूस की जा रही है। अच्छी बात है कि दल-बदल कानून पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गयी है। देखना होगा कि पुनर्विचार कब और कैसे होता है। लेकिन ऐसे किसी कानून से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जनतंत्र के नागरिक के मन में इस बात का जगना कि 'आया राम गया राम' का उदाहरण किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किया हो या राजनीतिक दल ने, यह पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था के साथ बेईमानी है। यह सच है कि ऐसा करते हुए 'शर्म' उनको मगर नहीं आती, पर जागरूक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह शर्म महसूस न करने वालों को शर्म दिलाने की कोशिश लगातार करता रहे। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसमें हमारे निर्वाचित नेता सविधान की शपथ लेने के साथ-साथ मतदाता के प्रति निष्ठा की भी शपथ लें। लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

धूमिल होते विपक्षी एकता के प्रयास

(लेखक - सुरेश हिंदुस्तानी)

आजकल वर्तमान केंद्र सरकार को सत्ताच्युत करने के सपने देखने की राजनीति गरम है। केंद्र में विपक्ष की राजनीति करने वाली कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय दल एक साथ चलने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक शैली को देखते हुए सजग ही यह सवाल देश के वातावरण में अटखेलियों कर रहा है कि क्या आज की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दल एक होकर चुनाव लड़ पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि सारे दल इस जोर आजमाइश में लगे हैं कि किसको कितनी सीट दी जाए। इस बारे में कांग्रेस के समक्ष बड़ी विकट स्थिति निर्मित होती जा रही है। क्योंकि जहां एक ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए एक और राजनीतिक यात्रा पर निकल चुके हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण स्वयं कांग्रेस की राजनीति ही है। क्योंकि उसके नेताओं को न ही अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान है और न ही उसके नेता वैसा आचरण ही कर रहे हैं। इसी कारण आज क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा प्रभावशाली हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के सहारे ही और कांग्रेस इस सत्य को अभी समझने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दे रही है। देश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह लगने लगा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आसनी होने की ओर अग्रसर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उनके प्रति भारत की जनता का जुड़ाव दिखाई देता है। इसी कारण

भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए जहां देश में विपक्ष के राजनीतिक दल एकता के लिए प्रयास करते दिखाई दे रहे थे, अब उन प्रयासों में बहुत बड़ा पेंच सामने आ गया है। यह पेंच इसलिए भी स्थापित हुआ है क्योंकि कांग्रेस को सारे क्षेत्रीय दल आंखें दिखाने की अवस्था में दिखाई देने लगे हैं। इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व बचाने का तर्क दिया जा सकता है, लेकिन सत्य यह भी है कांग्रेस वर्तमान में बहुत कमजोर हो गई है। इसलिए कांग्रेस को मन मुताबिक सीट देने को कोई भी दल तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस को उसकी स्थिति के अनुसार सीट देने को तैयार नहीं है। वहीं उत्तरप्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूढ़ में नहीं है। इंडी गठबंधन के लिए रही सही कसर पर नीतीश कुमार ने बिहार में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद स्वाभाविक रूप से विपक्षी एकता के गठबंधन को बहुत बड़ा आघात लगा है। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की एकता के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए थे, जिन्हें कांग्रेस द्वारा महत्व नहीं दिए जाने के कारण नीतीश कुमार ने अपनी अलग राजनीतिक राह निर्मित कर ली। वर्तमान में राजनीति रूप से अस्तित्व बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे विपक्षी दलों के समक्ष एक बार फिर से अपनी एकता को बनाए रखने के लिए चुनौतियां का पहाड़ स्थापित होता दिखाई दे रहा है। जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो आज के हालात को देखते हुए निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। विपक्ष के सारे दल किसी न किसी रूप में अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तू डाल डाल, में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ करते

हुए कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इससे एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के नेतृत्व को कोई भी दल सर्वसम्मति से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कांग्रेस का रवैया ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे उनका ही दल सब कुछ है। पश्चिम बंगाल और पंजाब की राजनीतिक स्वरो के निहितार्थ तलाशे जाएं तो यह कहने में कोई अतिरेक नहीं होगा कि कांग्रेस इन राज्यों में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए भी संभव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आधार और प्रभाव है और वह किसी भी प्रकार से अपने प्रभाव को कमजोर करने का काम नहीं करेगी, क्योंकि ममता के पास पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं भी राजनीतिक जमीन नहीं है। ऐसा ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा सकता है। इन दोनों दलों का व्यापक प्रभाव इन्हीं राज्यों में है, जिसे वह खोना नहीं चाहते। आज भले ही कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकता के प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है, जब कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ स्वीकार किया जाए, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान रवैयें को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता। एक समय गठबंधन के मुख्य सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा की तरफ कदम बढ़ाने की कवायद को विपक्षी एकता के लिए जबरदस्त आघात के रूप में ही देखा जा रहा है। ऐसा करने के पीछे अनुमान यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्वीकारोक्ति में वृद्धि की है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भले ही न्यायालय के आदेश पर हुआ हो, लेकिन इसके लिए भाजपा के योगदान को आज पूरा देश जानता है। आज बिहार की राजनीति

का अध्ययन किया जाए तो यह कहना ठीक ही होगा कि भले ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच बमेल गठबंधन बनाकर सरकार का संवाचन किया जा रहा था, लेकिन इन दोनों दलों के बीच विचारों की एकता नहीं थी। दोनों ही दल अपनी अपनी दाल पकाने में व्यस्त रहे। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने की राजनीति करने लगे थे।

इसी प्रकार की स्थिति उत्तरप्रदेश की है, जहां कांग्रेस की राजनीतिक जमीन शून्यता की ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उतना महत्व नहीं देगी, जितना वह चाहती है। इस प्रकार की परिस्थिति के बीच कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य की तस्वीर में किस प्रकार से रंग भरेगी, यह फिलहाल टैडी खीर ही कही जाएगी। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि विपक्ष की एकता जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके समक्ष एक एक करके बड़े अवरोध भी स्थापित हो रहे हैं। इस अवरोधों का सामना करने की हिम्मत एकता से ही संभव हो सकती थी, जो फिलहाल असंभव सा ही लग रहा है। ऐसा लगने लगा है विपक्षी एकता के प्रयास तार-तार हो रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी खामी यह भी है कि वह भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने की आत्मघाती भूल कर चुकी है। भगवान राम से भारत की जनता का सीधा संबंध है, जिसे कोई भी राजनीतिक दल नकारने का साहस नहीं कर सकता। विपक्षी राजनीतिक दलों को भविष्य की राजनीति की ओर कदम बढ़ाना है तो उसे भारत की आस्था को सम्मान देना ही होगा, नहीं तो जो स्थिति पहले हुई, वैसी ही स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। (वरिष्ठ पत्रकार)

भ्रष्टाचार और राजनीति

(लेखक - सनत जैन)

भ्रष्टाचार के आरोप अब राजनीति के सबसे बड़े अस्त्र साबित हो रहे हैं। पिछले चार दशक में राजनीति का एक नया स्वरूप देखने को मिला है। आरोप लगाओ, उस पर राजनीति करो, राजनीति के जरिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचो। आरोप झूठे हो या सच्चे हों, सजा हो या ना हो, लेकिन आरोपों की राजनीति में सत्ता का सिंहासन मिल जाता है। तो फिर इसको राजनीति के रूप में इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने वह बोफोर्स तोप में दलाली का आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर लगाया था। वह राजीव गांधी

मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे उनके द्वारा लगाए गए आरोप को काफी गंभीरता से लिया गया। भारतीय राजनीति में इसका बड़ा असर हुआ 1989 का लोकसभा चुनाव इसी बोफोर्स के आरोप में राजीव गांधी चुनाव हार गए। केंद्र में गठबंधन की दूसरी बार सरकार बनी। जिसमें कई राजनीतिक दल शामिल थे। विश्वास प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बोफोर्स के आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए। 1989 के बाद से लगातार गठबंधन की सरकार कई बार की संसदीय सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बोफोर्स घोटाले का सच आज तक सामने नहीं आया। हां जांच के नाम पर अरबों रुपये जरूर सरकार के खजाने

से खर्च हो गए। बोफोर्स तोप की दलाली में आज तक गांधी परिवार को दोषी नहीं ठहराया जा सका। लेकिन आरोप आज भी गांधी परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 2011 के बाद से एक बार फिर आरोपों की राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्र में जब तत्कालीन मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल के लोकलाफ ऑडिट में कई ऐसी मनगढ़ंत आरोप लगाए। जिन पर जांच भी हुई, उसके बाद भी उस पर किसी को सजा नहीं हुई। 2 जी टेलीकॉम घोटाला और कोयला घोटाला बड़ा चर्चित हुआ। लेकिन जांच में कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि काल्पनिक आरोप

लगाए गए थे। मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे आरोप लगाए गए जो आज तक साबित नहीं हो पाए हैं। लेकिन राजनीति में अभी भी कांग्रेस और उसके नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने के लिए उन्हीं आरोपों का बार-बार प्रयोग किया जाता है। 2014 के बाद से देश में जो राजनीति चल रही है। उसमें आरोपों को आधार बनाकर सीबाआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां लगातार जांच करती हैं। पिछले 10 वर्षों में किसी भी आरोप में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा तथा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार को बेचने के नाम पर आर्थिक

घोटाले की जांच पिछले कई वर्षों से की जा रही है। लेकिन इनकी जांच ही चल रही है। कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। वर्तमान कानून के हिसाब से उन्हें दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। अतः जांच के नाम पर कई वर्षों तक मामले को लटकाए रखना और चार्ज शीट पेश न करना राजनीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है। चारा घोटाले में कई वर्षों तक लालू यादव जेल में रह चुके हैं। डेढ़ दशक पहले के मामले को पुनः जांच में लेकर रावडी देवी, मीशा यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं सभी विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री और जो प्रमुख राजनेता हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इंडी और सीबीआई जांच शुरू कर दी है। कहा जाता है कि जो भाजपा में नहीं आता है, उनकी गिरफ्तारी इंडी कर लेती है। जमानत पर उन्हें दामिनी बना दिया जाता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन एवं मनीष सिंसोदिया को शराब घोटाले में कई महीनों से जेल में बंद करके रखा गया है। कोर्ट में चार्ज शीट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। कई महीनों तक नेता जेल में बंद रहते हैं। केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और अब मीडिया आरोपों को लेकर एक माहौल बनाता है। भारत के सभी विपक्षी दल इस

समय भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए हैं, यह छवि विपक्षी नेताओं की बना दी गई है। सबसे बड़े आक्षेप की बात यह है, कि किसी भी मामले में चार्ज शीट पेश नहीं की जाती। बिना जांच के भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए जाते हैं। विशेष कानून के तहत इसकी जांच शुरू हो जाती है। जांच और गिरफ्तारी के नाम पर जो राजनीति हो रही है। उसने भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही बदल दिया है। न्यायपालिका में भी आरोपों के आधार पर जो राजनीति हो रही है। कई महीनों तक जेल में बंद रखने के बाद भी, जब जांच एजेंसियां सबूत भी पेश नहीं कर पाती हैं। उस समय न्यायपालिका का मौन यह साबित करता है।



चना का रकबा घटने से कीमतों में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली । चना के भाव फिर से बढ़ने लगे हैं। इसकारण चना का रकबा घटने से उत्पादन में कमी आने की संभावना है। साथ ही श्राद्धियों के सीजन के लिए स्टॉकिस्टों और दाल मिलों द्वारा इसकी खरीद बढ़ाने पर जोर देना है। आने वाले दिनों में भी चना की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इन दिनों चने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते 10 दिन के दौरान प्रमुख मंडियों में चना के थोक भाव 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं। दिल्ली में चना की थोक कीमत 5,800-5,850 रुपये से बढ़कर 6,100-6,125 रुपये, मध्य प्रदेश की गंजबासीदा मंडी में 5,200-5,400 रुपये से बढ़कर 5,400-5,700 रुपये और महाराष्ट्र की लातूर मंडी में 5,800-5,850 रुपये से बढ़कर 6,100-6,150 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। कर्माडिटी जानकारी के मुताबिक चने के दाम बढ़कर 6,350 से 6,400 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 102.90 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि के रकबा 109.73 लाख हेक्टेयर से करीब 6 फीसदी कम है। इसकारण इस साल चने की पैदावार में 15 फीसदी गिरावट आ सकती है। उत्पादन घटने की आशंका में चने की कीमतों में तेजी आ रही है। नेफेड के पास वर्तमान में चना का करीब 10 लाख टन और निजी कारोबारियों के पास करीब 5 लाख टन का स्टॉक बचा है, जो मांग के हिसाब से सीमित स्टॉक कहा जा सकता है। बाजार जानकारों के मुताबिक आगे श्राद्धियों के सीजन में दाल मिलों की ओर से चने का मांग और बढ़ सकता है।

डेलावेयर कोर्ट से मस्क को झटका, 465 करोड़ का पैकेज रद्द

सैन फ्रांसिस्को । टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का 465 करोड़ रुपए का पैकेज कोर्ट ने रद्द किया है। डेलावेयर कोर्ट की जज ने मस्क के पैकेज कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर कहा कि कंपनी इस बात पर काम करे कि मस्क अभी तक मिले अतिरिक्त वेतन को कैसे लौटाएंगे। जज ने कहा कि मस्क को पब्लिक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज मिल रहा है। यह एक अथाह राशि है और इस देने से पहले कंपनी के बोर्ड ने विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मस्क के पैकेज प्लान को मंजूरी देने की प्रक्रिया में बड़ी खामियां थीं। इसके बाद टेस्ला के शेयर में लगभग 3 फीसदी की गिरावट आई की गई। दरअसल 5 साल पहले कुछ शेयर होल्डर्स ने मस्क और टेस्ला के बोर्ड पर कॉर्पोरेट संपत्तियों को बर्बाद करने और एलन मस्क को गैरकानूनी रूप से अमीर बनाने का आरोप लगाया था। मस्क के पास टेस्ला की लगभग 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। कोर्ट में शेयरहोल्डर के वकील ने कहा कि कंपनी ने एलन का पैकेज डिस्माइड करने से पहले एक दिखावटी नेगोशिएशन किया। इसके लिए किसी भी शेयर होल्डर से कंपनी बोर्ड ने सलाह नहीं ली। वकील ने कहा कि टेस्ला ने शेयर होल्डर्स को गुमराह किया है।

ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेपाल ने शुरु की कर्मचारियों की छंटनी

मुंबई । ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेपाल ने छंटनी शुरु कर दी है, जिससे करीब 9 प्रतिशत कार्यबल यानी लगभग 2,500 कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं। पोस्ट के अनुसार, कृपया अपने साथी पेपाल कर्मचारियों का सपोर्ट करें। पेपाल कर्मचारियों को गुगल की शुभकामनाएं। पेपाल के सीईओ एलेक्स क्रिस ने एक आंतरिक ज्ञापन में कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को सहाह के अंत तक सूचित किया जाएगा। पेपाल को एप्पल, जेले और ब्लॉक जैसे प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल लगभग इसी समय, पेपाल ने लगभग 2,000 कर्मचारियों यानी अपने कार्यबल के 7 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की थी। ऑनलाइन पेमेंट्स कंपनी ने कहा कि उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पेपाल ने एक बयान में कहा, जैसे-जैसे हमारी दुनिया, हमारे कस्टमर्स और हमारा प्रतिस्पर्धी परिदृश्य विकसित हो रहा है, हमें बदलाव जारी रखना चाहिए।

मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ टाटा मोटर्स फिर बनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी

नई दिल्ली ।

सात साल बाद मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ टाटा मोटर्स एक बार फिर भारत की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टाटा मोटर्स का स्टॉक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। दोपहर 01:01 बजे बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर का कुल मार्केट कैप 3.16 ट्रिलियन रुपये था, जबकि मारे ति सुजुकी का मार्केट कैप थोड़ा कम 3.15 ट्रिलियन रुपये था। कैपिटललाइन डेटा के मुताबिक, 25 जनवरी 2017 को टाटा मोटर्स का मूल्य 1.76 ट्रिलियन रुपये था, जबकि मारे ति सुजुकी का मूल्य 1.75 ट्रिलियन रुपये था। आज टाटा मोटर्स के शेयर

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, टाटा मोटर्स 3 प्रतिशत बढ़कर 864.70 रुपये पर और टाटा मोटर्स डीवीआर 2 प्रे तिशत बढ़कर 574.95 रुपये पर पहुंच गया। इसके विपरीत मारुति सुजुकी का शेयर 10,005 रुपये पर स्थिर रहा। इस बीच, एसएंडपी बीएसई संसेक्स 0.40 प्रतिशत गिरकर 71,653 पर था। पिछले एक साल में, टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मारुति सुजुकी में 13.5 प्रे तिशत की वृद्धि देखी गई। इसी अवधि के दौरान एसएंडपी बीएसई संसेक्स 21 प्रे तिशत बढ़ गया। टाटा मोटर्स ने अपनी यूके स्थित सहायक कंपनी जगुआर लैंड रॉवर जेएलएलर में ज्यादा बिक्री के कारण बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया है। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में ज्यादा लोगों के कार



खरीदने, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और कम लागत से टाटा मोटर्स को मदद मिलेगी। दिसंबर में 148,000 ऑर्डर के साथ जेएलएलर की ऑर्डर बुक अभी भी मजबूत है। हालांकि, ये सितंबर में 168,000 ऑर्डर से कम है। इसका मतलब है कि वे तेजी से कारों की डिलीवरी कर रहे हैं, विशेष रूप से रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पॉट और डिफेंडर जैसे लोकप्रिय मॉडल खूब बिक रहे हैं, जो ऑर्डर का 76 प्रतिशत हिस्सा हैं।

मोबाइल फोन की कीमतों में होगी कमी, मोदी सरकार ने लिया फैसला

मुंबई ।

बजट से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है। अब इनके आयात पर 10 फीसदी की ड्यूटी लागू होगी। पहले मोबाइल पार्ट पर 15 फीसदी की ड्यूटी चुकानी होती थी। इन कपोनेंट्स में बैटरी एनक्लोजर्स, प्राइमरी लेंसेज, रियर कवर्स के साथ प्लास्टिक और मेटल से बने कई मैकेनिकल कपोनेंट्स शामिल

हैं। अगले वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का जो फैसला किया है, उससे मोबाइल फोन सेक्टर को तगड़ा मुनाफा होगा। इससे न सिर्फ सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा बल्कि वैश्विक मार्केट में कॉम्पटीशन भी बढ़ेगा। मोदी सरकार के इस फैसले से एपल जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल इंडस्ट्री करीब



12 कपोनेंट्स पर ड्यूटी घटाने की वकालत कर रही है ताकि भारत में स्मार्टफोन बनाने की लागत कम की जा सके। इसके अलावा यह मांग चीन और वियतनाम जैसे पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी देशों के खिलाफ अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोबाइल कैमरा फोन के कुछ कपोनेंट्स पर 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया था।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के तीसरे ही कारोबारी दिन एशियाई और अन्य बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीददारी से बाजार तरोप आया। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई संसेक्स 612.21 अंक करीब 0.86 फीसदी बढ़कर 71,752.11 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी भी 203.60 अंक तकरीबन 0.95 फीसदी ऊपर आकर 21,725.70 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान सन फार्मा, टाटा मोटर्स, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा

एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर बढ़े। वहीं दूसरी ओर लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) का शेयर चार फीसदी से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुआ। दिसंबर तिमाही के परिणाम उम्मीदों के अनुसार नहीं रहने से भी कंपनी के शेयर गिरे हैं। इसके अलावा, टाइटन भी टूट। शॉर्गॉ कंपोजिट, हैंग सेंग, कोसमी और ताडवान 0.3 से 0.5 फीसदी के बीच कारोबार करते दिखे। वहीं अमेरिकी बाजार की बात करें तो डॉव जोन्स 0.4 फीसदी बढ़कर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 0.8 फीसदी गिरा। एसएंडपी 500 0.1 फीसदी नीचे फिसला। इससे पहले आज सुबह घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बाजार में ये गिरावट एशियाई और अन्य बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही बिकवाली



हावी रहने से आई है। बजट को लेकर निवेशकों ने भी सतर्क रुख अपनाया और इसके अलावा वे अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति के परिणामों को लेकर भी आशंकित दिखे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई संसेक्स 70,846 के निचले स्तर तक गिरने के बाद 71,229 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 0 21,550 के स्तर के आसपास कारोबार करता दिखा।

एसी और कर्मर्शियल रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी का शुद्ध लाभ 72 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई ।

एयर कंडीशनर (एसी) और कर्मर्शियल रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ वार्षिक वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) में 72 प्रतिशत उछाल के साथ 100.46 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 58.41 करोड़ रुपये रहा था। ब्लू स्टार लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इसी तिमाही में उसकी परिचालन आय 25 प्रतिशत बढ़कर 2,241.19 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,794.17 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि ब्लू स्टार ने त्रैहारी सीजन के दौरान अपने कमरे वाले एसी और कर्मर्शियल रेफ्रिजरेटर उत्पादों की मजबूत मांग देखी। ब्लू स्टार का कुल खर्च इसी तिमाही में 23.3 प्रतिशत बढ़कर 2,119.57 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी की कुल आमदनी 25.26 प्रतिशत बढ़कर 2,253.86 करोड़ रुपये रही है। ब्लू स्टार की इलेक्ट्रो-मैकेनिकल परियोजनाओं और कर्मर्शियल एसी सेगमेंट से आमदनी दिसंबर, 2023 तिमाही में 17.87 प्रतिशत बढ़कर 1,182.30 करोड़ रुपये रही है। पेशेवर इलेक्ट्रोनिक्स और औद्योगिक तंत्र



अयोध्या के लिए 1 फरवरी से स्पाइस जेट शुरू करेगी 8 नई उड़ानें

नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत को देखते हुए अब यहां स्पाइस जेट ने 1 फरवरी से 8 नई उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है। राम मंदिर के दर्शन की इच्छा रखने वाले राम भक्तों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट अपनी 8 फ्लाइट्स शुरू करने जा रही है। अभी तक सिर्फ इंडिगो और एअर इंडिया ही अयोध्या के लिए अपनी लिमिटेड उड़ान सर्विस दे रही हैं। स्पाइसजेट देश के अलग-अलग शहरों से अयोध्या के लिए 1 फरवरी, 2024 से 8 फ्लाइट्स शुरू करेगी। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ये फ्लाइट्स दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद,



जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बंगलुरु से सीधी चलेगी। गौरतलब है कि अयोध्या में इसी महीने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। इस बीच, घरेलू एयरलाइन 'जुम' ने भी बुधवार 31 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट्स के साथ अपनी सर्विस बहाल कर दी है। एयरलाइन ने मंगलवार को बयान में कहा

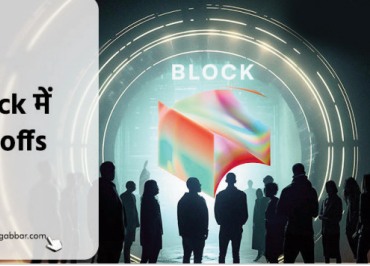
कि पहली फ्लाइट्स के तहत दिल्ली-अयोध्या रूट पर बॉम्बार्डियर सीआरजे 200 ईआर विमान को तैनात करेंगी। हाल ही में अकासा एयर ने भी अयोध्या के लिए फ्लाइट्स शुरू करने की घोषणा की है। अकासा एयरलाइंस पुणे से अयोध्या वाया दिल्ली के बीच फ्लाइट शुरू कर रही है, जो कि 15 फरवरी 2024 से चलेगी।

जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक ने लगभग 1,000 कर्मचारियों को किया बाहर

सैन फ्रांसिस्को ।

जैक डोर्सी की फाइनेंशियल कंपनी ब्लॉक ने करीब 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी की इस कार्रवाई से अनेक विभागों में असर हुआ है, जिससे कंपनी के केश एप, आफ्टरपे और स्क्रापर सब्सिडियरी कंपनियों के कर्मचारी भी प्रभावित हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,000 कर्मचारी, यानी कंपनी के कार्यबल के 10 प्रतिशत लोग इस निर्णय से प्रभावित हुए। इस संबंध में डोर्सी ने इंटरनल मेमो में लिखा कि हम जानते हैं कि हमें कार्रवाई करने की जरूरत है, हम इसे तुरंत कर लेना चाहते हैं न कि चीजों को हमेशा के लिए यूं ही पड़े रहने देना चाहते हैं। बता दें कि पिछले साल ब्लॉक ने कहा था कि वह 2023

की तीसरी तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या 13,000 से घटाकर इस साल के अंत तक 12,000 तक कर देगा। पीयर-टू-पीयर पेमेंट सर्विस केश एप के राजस्व में काफी गिरावट आई है। इस बात, इसकी बाय नाइ, पे लेंटर (बीएनपीएल) सर्विस आफ्टरपे, जिसे ब्लॉक ने 2021 में 29 बिलियन डॉलर में हासिल किया था, ने गंभीर नुकसान उठाना है। दरअसल स्क्रापर को कई मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसमें फिसर्व के क्लोवर, टोट्ट और स्ट्रुइप शामिल हैं। ब्लॉक ने 2023 की तीसरी तिमाही में 5.62 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जिसमें बिटकॉइन होल्डिंग्स पर 44



मिलियन डॉलर का लाभ हुआ। पिछले साल सितंबर में, डोर्सी को ब्लॉक का प्रमुख और अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसकी उन्होंने 2009 में सह-स्थापना की थी। डोर्सी का पद तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष और चेयरपर्सन से बदलकर ब्लॉक प्रमुख और चेयरपर्सन कर दिया।

विकास दर के मामले में चीन और अमेरिका से कई गुना आगे रहेगा भारत

नई दिल्ली । बजट सत्र से पहले आईएमएफ ने विकास दर की रिपोर्ट जारी की। भारत में विकास दर 6 फीसदी रहने का अनुमान है। चीन और अमेरिका में विकास दर 3 फीसदी से भी कम रहेगी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को बदल दिया है, उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो पिछले अनुमान 6.3 प्रतिशत से अधिक है। जनवरी के लिए आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट ने सकारात्मक संशोधन में योगदान देने वाले प्रमुख कारक के रूप में भारत की बढ़ती घरेलू मांग पर प्रकाश डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विकास दर 2024 और 2025 दोनों में 6.5 प्रतिशत पर मजबूत रहने का अनुमान है, अक्टूबर से दोनों वर्षों के लिए 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ, घरेलू मांग में लचीलेपन को दर्शाता है। दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले वित्त वर्ष 24 में भारत के लिए 7.4 प्रतिशत की थोड़ी अधिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को भी आईएमएफ ने सकारात्मक दृष्टिकोण मिला। आईएमएफ तंग मौद्रिक स्थितियों के बावजूद, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बढ़े हुए खर्च को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार का श्रेय देता है। इसके अतिरिक्त, उच्च श्रम बल भागीदारी, बहाल आर्गुति श्रृंखला और कम ऊर्जा और कर्माडिटी की कीमतें जैसे कारक सकारात्मक पूर्वानुमान में योगदान करते हैं।

नौ महीनों में भारत ने भारी मात्रा में आयात किया स्टील

नई दिल्ली ।

मार्च में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत ने भारी मात्रा में स्टील का आयात किया, जो पांच साल के शीर्ष स्तर है।

रिपोर्ट किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इससे भारत तैयार स्टील का शुद्ध आयातक बन गया। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बेहतर बुनियादी ढांचे ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टील उत्पादकों दोनों के लिए एक आकर्षक बाजार बना दिया है। इसके विपरीत, यूरोप और अमेरिका में स्टील की मांग घट रही है। अप्रैल और दिसंबर के बीच, भारत ने 5.6 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील का आयात किया, जो पिछले वर्ष से 26.4 प्रतिशत अधिक है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे स्टील उत्पादक भारत में स्टील की खपत इस दौरान छह साल के शीर्ष स्तर 100 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गई, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में मजबूत मांग को दर्शाता है।

भारत में स्टील की मांग ऊंची रहने की उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार का अनुमान है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि वैश्विक वृद्धि से अधिक हो जाएगी। जबकि

भारतीय स्टील मिलों ने बढ़ते आयात के खिलाफ सरकारी समर्थन और सुरक्षात्मक उपायों का अनुरोध किया है, स्टील मंत्रालय ने मजबूत स्थानीय मांग का इवाला देकर प्रतिबंध लगाने से इंकार किया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी के प्रमुख ने बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने बारीकी से नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि भारत में स्टील की डिपिंग से स्टील उद्योग के मुनाफा और निवेश योजनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

अप्रैल और दिसंबर के बीच, दक्षिण कोरिया भारत को तैयार स्टील का प्रमुख निर्यातक था, जिसने 1.77 मिलियन मीट्रिक टन एलॉय भेजी। इसमें पिछले वर्ष की वृद्धि हुई और यह चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दुनिया के अग्रणी स्टील उत्पादक चीन को पीछे छोड़ते हुए, दक्षिण कोरिया ने भारत को 1.77 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील बेचा, जो चार साल का उच्चतम स्तर है। इस बीच, अप्रैल और दिसंबर के बीच भारत का तैयार स्टील निर्यात कुल 4.7 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो कम से कम छह वर्षों में सबसे कम है, जो कमजोर विदेशी मांग का संकेत देता है।

सुजलॉन एनर्जी को मिला 642 मेगावाट की पवन परियोजना का ठेका

-ऑर्डर मिलते ही शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 3.7 फीटसी की हुई बढ़ोतरी



नई दिल्ली ।

रिन्ड्यूएबल एनर्जी सोल्यूएशन प्रोवाइडर सुजलॉन ग्रुप को 642 मेगावाट की पवन परियोजना का ठेका मिलते ही शेयरों में उछाल आ गया है। जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयर मंगलवार को इंट्राडे कारोबार में 3.7 प्रतिशत चढ़ गए। जबकि ये शेयर सोमवार को 43.27 रुपये पर बंद हुए थे। बता दें कि कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे बड़ा कारण है। दरअसल सुजलॉन ग्रुप को एवरेन कंपनी को पीछे छोड़ते हुए, दक्षिण कोरिया में भारत को 1.77 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील बेचा, जो चार साल का उच्चतम स्तर है। इस बीच, अप्रैल और दिसंबर के बीच भारत का तैयार स्टील निर्यात कुल 4.7 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जो कम से कम छह वर्षों में सबसे कम है, जो कमजोर विदेशी मांग का संकेत देता है।

पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) स्थापित करेगा। सुजलॉन समूह के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने एक बयान में कहा कि सुजलॉन भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के तहत हरित ऊर्जा खंड को बढ़ाने के लिए एवरेन के साथ साझेदारी को प्रतिबद्ध हैं। वहीं सुजलॉन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.पी. चालासानी ने कहा कि हमें एवरेन के साथ अपने पहले ठेके की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यहां गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में सुजलॉन ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर में पिछले सात दिनों के दौरान 7 फीसदी का इजाफा हुआ है जबकि एक्सिस एनर्जी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ठेके के तहत सुजलॉन आंध्र प्रदेश में हाइब्रिड लैंडट ट्यूबलर (एचएलटी) टावर और 214

पर्यटन का खास मुकाम डल झील

डल झील श्रीनगर, कश्मीर में तो प्रसिद्ध है ही लेकिन दुनिया भर के सैलानियों के लिए भी यह पर्यटन का एक खास मुकाम है। कहा जाता है कि इसमें खेतों से जल आता है एवं यह झील खुद ही कश्मीर घाटी में काफी झीलों से जुड़ी हुई है। यह दुनिया भर में शिकारों या हाऊस बोट के लिए जानी जाती है और सैलानी खासतौर पर इनका आनंद लेने के लिए यहां आते हैं। यह 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तीन दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है और भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसे शामिल किया जाता है। पर्यटक जम्मू-कश्मीर आएँ और डल झील देखने न जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। डल झील के पास ही मुगलों के सुंदर एवं प्रसिद्ध पुष्प वाटिका से झील की आकृति और उभरकर सामने आती है। मुख्य रूप से इस झील में मछली का काम होता है। डल झील के मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहां के हाउसबोट। सैलानी इन हाउसबोटों में रहकर इस खूबसूरत झील का आनंद उठा सकते हैं। झील, कश्मीर की घाटियों की अन्य धाराओं के साथ मिल जाती है। झील के चार जलाशय हैं गगरीबल, लोकूट डल, बोड डल तथा नागिन। लोकूट डल के मध्य में स्प लंक द्वीप स्थित है, तथा बोड डल जलधारा के मध्य में सोना लंक स्थित है। वनस्पति डल झील की खूबसूरती को और निखार देती है। कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी, झील की सुंदरता को दुगुना कर देती है। सैलानियों के लिए झील के सौंदर्य के अलावा भी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन यहां पर उपलब्ध हैं। जैसे कि कायाकिंग, केनोइंग डोगी

पानी पर सर्फिंग करना व एंगलिंग मछली पकड़ना आदि से सफर और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। कश्मीर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय झील के तट पर स्थित है। हाउसबोट में रहकर सैलानी इस झील के खूबसूरत वातावरण से भावविभोर हो जाते हैं। शिकार के माध्यम से सैलानी नेहरूपार्क, कानुदर खाना, चारचिनारी, कुछ द्वीप जो यहां पर स्थित हैं, उन्हें देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए हजरतबल तीर्थस्थल के दर्शन करे बिना उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। शिकार के माध्यम से श्रद्धालु इस तीर्थस्थल के दर्शन कर सकते हैं। एक शिकार पर सवार होकर विभिन्न प्रकार की कश्मीरी चीजें भी खरीद सकते हैं और दुकानों भी शिकार पर ही लगी होती हैं। यह मात खरीददार तक ही सीमित नहीं है, परन्तु एक रोमांचित कर देने वाला खेल भी होगा।



कैसे जाएं:

यदि पर्यटक डल झील पहुंचना चाहते हैं, तो श्रीनगर जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर बडगाम जिले में स्थित एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। नजदीक रेल सेवा जम्मू में स्थित है, तथा वहां का नेशनल हाईवे एनएचए कश्मीर घाटी को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। इन पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करने के लिए दस से बारह घंटे लगते हैं। इस सफर के दौरान पर्यटक यहां के प्रसिद्ध जवाहर टनल को निहार सकते हैं।

धर्मशाला में उठायें बर्फली पहाड़ियों का रोमांच

पहाड़ियों में चीड़ व देवधर के घने जंगलों और बर्फ की करीब से देखने का अनुभव धर्मशाला में मिलता है। यहां सीधे-सादे और बौद्ध धर्म के बिरले चिह्न भी यहां आसानी से देखने को मिलते हैं। धर्मशाला में झरने व सुहाने नजारों इस जगह को सभी की पसंद बनाते हैं। हालांकि अब यहां तिब्बत के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल का प्रभाव इस छोटे शहर पर आज भी महसूस किया जा रहा है। खूबसूरत पहाड़ी शहर धर्मशाला को यूं तो अंग्रेजों ने बसाया था, लेकिन अब तिब्बतियों की संख्या ज्यादा होने से इस पर वहां के कन्चर का इतना प्रभाव पड़ा है कि इसे लिटल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की पहाड़ियों में बसा धर्मशाला देश-विदेश के सैलानियों का पसंदीदा हिल स्टेशन है। इसे साल 1855 में अंग्रेज ने इसे बसाया था। दरअसल, यह उन 80 रिजॉर्ट्स में से था, जिन्हें अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए तैयार करवाया था। गद्दी, तिब्बती, टेकर्स, टूरिस्ट और लोकल वेंडर्स, सब मिलकर निचले धर्मशाला यानी कोतवाली बाजार में एक अलग ही माहौल बनाते हैं। यह जगह समुद्र तल से 1250 मीटर की ऊंचाई पर है। लोगों का खूब आना-जाना होने की वजह से यहां खासी हलचल रहती है। समुद्र तल से 1768 मीटर की ऊंचाई पर बसे ऊपरी धर्मशाला यानी मैकलॉडगंज में दलाई लामा का निवास है। दोनों जगह की दूरी 10 किलोमीटर है। जहां तक घूमने की बात है, तो धर्मशाला में आपको अडवेंचरस व स्पिचुअल माहौल मिलेगा। ठंडी पहाड़ी हवाओं में गुंजती प्रार्थनाओं की आवाजें मन को एक ठहराव देती हैं। ऐसे में बेशक धर्मशाला जाना दलाई लामा से मुलाकात के बिना अधूरा है और यकीन मानिए इस माहौल में उनका साथ किसी भी इंसान को कुछ देर के लिए एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वैसे, धर्मशाला की तमाम मोनेस्ट्रीज एक बार देखने लायक जगह हैं और अलग-अलग समाधियों में भगवान बुद्ध की तांबे की प्रतिमाएं भी दर्शनीय हैं। अब जब इतना कुछ एक ही जगह पर मौजूद है तो देश-विदेश के पर्यटकों का सहज ही धर्मशाला की ओर खिंचे आना हैरानी की बात नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यहां के तुशिता मेडिटेशन सेंटर में मॉक्स द्वारा दी जाने वाली क्लासेज जॉइन

धौलाधर की पहाड़ियों में ट्रेकिंग व रॉक क्लाइंबिंग जाने के लिए धर्मशाला शुरूआती पॉइंट है। यहां कई नदियों व झरनों में एंगलिंग व फिशिंग का मजा लिया जा सकता है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट गगला है, जिसकी यहां से दूरी 13 किलोमीटर है।

की जा सकती है। यहां आपको साफ-सुथरे आवास की सुविधा भी मिलेगी। मेडिटेशन सीखने के बाद नेचुंग मोनेस्ट्री में 3किलोमीटर बना म्यूजियम देख सकते हैं। नोबरलिंगा इंस्टीट्यूट में आप नए आर्टिस्ट्स को थंका पेंटिंस सीखते देख सकते हैं। अगर आप दाल, चावल, रोटी और सैंडविच खाकर बोर हो गए हैं तो यहां आप बेहतरीन तिब्बती खाने का मजा ले सकते हैं। यहां के कई रेस्तरांओं में आपको लजीज मोमोज व थुकुसा खाने को मिलेंगे। खाने का लुफ्त लेने के बाद आप लंबी वॉक, ट्रेकिंग और खूबसूरत नजारों में पिकनिक का मजा ले सकते हैं। यहां से 8 किलोमीटर आगे आपको ब्रिटिश राज का मेमोरियल चर्च ऑफ सेंट जॉन-इन-द विल्डरनेस देख सकते हैं। इसे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड एलगिन के नाम पर बनाया गया है। निचले धर्मशाला में बना कांगड़ा आर्ट म्यूजियम कांगड़ा के सालों पुराने इतिहास को दिखाता है। म्यूजियम की एक गैलरी में आपको कांगड़ा की मशहूर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मिट्टी के बर्तन और एंथ्रोपॉलजी से जुड़ी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। धर्मशाला के एंटी पॉइंट पर आपको एक वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा, जिसे स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद होने वाले जवानों की याद में बनवाया गया है। धर्मशाला में धर्मकोट व डल लेक जैसे पिकनिक स्पॉट्स भी हैं और यहां सितंबर के महीने में हर साल एक बड़ा मेला भी लगता है। इसी के पास भगसुनाथ की श्राइन भी है। इस पुराने मंदिर के पास से बहते ताजे पानी से झरने इस जगह को एक अलौकिक नजारा बना देते हैं। देवी कुणान पथरी को समर्पित मंदिर, ततवानी के गर्म पानी के झरने और मछरैल के बड़े बोटफॉल भी देखने लायक जगह हैं। अगर वुड वर्क में विलचस्पी रखते हैं तो नॉर्बुलिका इंस्टीट्यूट जरूर जाएं। यहां हो रहे काम की आर्ट को देखकर निश्चित तौर पर आप हैरान रह

जाएंगे। स्वामी चिन्मानंद द्वारा बनाया गया चिन्मय तपोवन भी एक दर्शनीय जगह है। बिंदु सारस के किनारे बसे इस आश्रम में आपको नौ मीटर ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, राम मंदिर, मेडिटेशन हॉल वगैरह दिखेंगे। धौलाधर की पहाड़ियों में ट्रेकिंग व रॉक क्लाइंबिंग जाने के लिए धर्मशाला शुरूआती पॉइंट है। यहां कई नदियों व झरनों में एंगलिंग व फिशिंग का मजा लिया जा सकता है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट गगला है, जिसकी यहां से दूरी 13 किलोमीटर है। यहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन पटानकोट है, जहां से धर्मशाला 85 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यहां चंडीगढ़, कीरतपुर और बिलासपुर होते हुए पहुंचा जा सकता है। तिब्बती नए साल यानी मार्च के आस-पास यहां बहुत टूरिस्ट आते हैं। वैसे, मई से अक्टूबर के बीच ट्रेकिंग सीजन रहता है। धर्मशाला में हैंडीक्राफ्ट मसलन तिब्बती कार्पेट, टेक्सटाइल, टूडिशानल, हेट्स, बैग्स, ट्राउजर्स, मेटलवर्क, जूली, जैकेट व हाथ से बने कार्डिगन आदि के शौकीनों के लिए ढेर सारी जगहें हैं।



एलियन के हमलों से खुद को बचा नहीं पाएगा अमेरिका

—अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बयान में किया साफ



वॉशिंगटन। हाल ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (डीओडी) एक बयान में साफ किया है कि अमेरिका एलियन अग्र हमला करता है तो वह ऐसे हमलों से खुद को बचा नहीं पाएगा। यह बयान अमेरिका को अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फिनोमिना (यूएपी), जिसे पहले यूएफओ कहा जाता था, के संभावित खतरों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता का विश्लेषण करने के बाद दिया गया है। यहां यह जानना जरूरी है कि अमेरिकी रक्षा विभाग, पैट्रान ने जुलाई 2022 में ऑल डोमेन एनामोलो रिजोल्यूशन ऑफिस (आरो) का गठन ऐसे ही मामलों के लिए किया था। अब ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने साफ किया है कि अभी अमेरिका में एलियन के हमले से निपटने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। यह बयान पिछले साल अगस्त में जारी इवेलनयूश न ऑफ डीओडी एवशान्स रिगार्डिंग अनआइडेंटिफाइड एनामोलस फिनोमिना नाम की क्लासिफाइड रिपोर्ट के सारांश के आधार पर दिया गया है। बयान के मुताबिक डीओडी एलियन से पैदा हुए किसी भी तरह के खतरों से निपटने में सक्षम नहीं है। यह साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि डीओडीमें ऐसे सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एलियन की ओर से आए खतरों से निपटने के लिए ब्यापक और संयोजक तरीका नहीं है। यह सारांश इसलिए जारी किया गया है जिससे लोगों को पारदर्शिता के तौर पर पता हो कि इस मुद्दे पर क्या स्थिति है। इस्पेक्टर जनरल रॉबर्ट पी स्टीवेंस का कहना है कि इस तरह के बयान देने का मकसद अमेरिकी लोगों के प्रति सही पारदर्शिता बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, प्रक्रियाएं, नीतियां आदि से संबंधित भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, जरूरतों, और संयोजन आदि निर्धारित करने की जरूरत है। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने खिलाफ किसी भी तरह से खतरों से निपटने के लिए कितना गंभीर है। ओआईडी ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को इसके लिए जरूरी नीतिगत सुझाव भी दिए हैं जिससे इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।

भारतीय मूल के युवक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

ओटावा। कनाडा के एक शहर में भारतीय मूल के एक युवक की हत्या करने के आरोप में एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस मामले की जांच में मदद के लिए अन्य तथ्य जुटाने और सीडियो फुटेज खंगालने में लगी हुई है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रेमटन शहर में रहने वाले 18 वर्षीय निराश्रित को पिछले वर्ष 19 दिसंबर को वहां के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई। पीत क्षेत्रीय पुलिस ने एक बयान में बताया, उसे किसी अज्ञात स्थान व समय पर गोली मारी गई और बाद में अस्पताल में छोड़ दिया गया था। बयान के मुताबिक, थिंड की मौत के बाद पीत क्षेत्रीय पुलिस के हेमिसाइड ब्यूरो के कर्मियों ने नौ जनवरी को ब्रेमटन के एक घर पर थोपमारी की और बाद में 18 वर्षीय प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं तथ्यों की जांच के बाद उत्तर अंपराध को अंजाम देने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। ब्रेमटन की ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष पेश करने से पहले उसे पुलिस ने हिरासत में रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गोली चलाने वाला सदियु ब्रेमटन का रहने वाला 16 वर्षीय एक किशोर है जो हत्या के मामले में कनाडा में भी वांटेड अपराधी है।

मालदीव के अभियोजक जनरल को बदमाशों ने बेरहमी से मारा चाकू

माले। मालदीव के अभियोजक जनरल हुसैन शमीम को अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से चाकू मार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शमीम की निष्पत्ति मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने की थी, जो पिछले साल नवंबर तक सरकार में थी और वर्तमान में विपक्षी पार्टी है। शमीम पर यह हमला तब हुआ जब हाल के दिनों में सड़क पर गिराहों द्वारा मालदीव के कई सांसदों को निशाना बनाया गया है। यह घटनाक्रम होते ही मालदीव की संसद में अफरा-तफरी मच गई। इससे पहले जब सांसदों ने मारपीट की और मुद्दजु के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र को बाधित कर दिया। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद एमडीपी से भिड़ गए। बाद में 21 फरवरी को मालदीव के संसद लेने के तुरंत बाद, मुद्दजु ने औपचारिक रूप से सत्र से 15 मार्च तक अपने देश से 88 सैन्य कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मालदीव के लोगों ने उन्हें नहीं दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया था।

रेगिस्तान में इस मालगाड़ी का 16 घंटे का सफर रोमांचक



मॉरिटानिया। रेगिस्तान में एक मालगाड़ी का 16 से 20 घंटों का सफर किसी रोमांचक रेल यात्रा से कम नहीं होता है। पश्चिम अफ्रीका के मॉरिटानिया में लोहे की खदानों के लिए चलने वाले इकलौते यातायात साधन के रूप में चलने वाली ट्रेन के सफर को रेल अलग तरह से मजा लेते हैं। लेकिन ये सफर मुश्किलों से भरा भी है। सहारा रेगिस्तान में एक लंबी मालगाड़ी की यात्रा को अनोखा ही कहा जा सकता है। गाड़ी में सफर करना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। मालगाड़ी होने के बाद भी इसमें लोग सफर करते हैं और परेशानियां होने के बाद भी इसका अपना रोमांच है। मॉरिटानिया रेलवे 1963 से पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से लौह खनिज को ढोने का काम कर रही है। 1704 किमीमीटर लंबा एकल ट्रेक नौआदिबो शहर से जोएरात की खानों तक जाता है। एक ओर के सफर में 16 से 20 घंटों का समय लगता है और यह कई बार लंबा भी हो जाता है। ट्रेन के बारे में रोचक बात यहां है कि इसके आने जाने का समय तय नहीं है, लेकिन यह हमेशा दोपहर के समय आती है और यात्री नौआदिबो स्टेशन पर एक बजे से लेकर 5 बजे तब इंतजार करते दिखाते हैं। यहां पर लोग खाने के सामान जैसे की चावल, सब्जियां, खजूर पेय पदार्थों की बोतलें आदि ट्रेन में चढ़ाते हैं। लोहे की खदानों के पास हजारों लोग रहते हैं लेकिन यातायात के लिए केवल रेल पर निर्भर हैं। क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसके बाद भी ट्रेन का मकसद लौह खनिज को नौआदिबो तक ढोना है जहां से वह चीन, यूरोप और अन्य देशों को जाता है। लौह खनिज मॉरिटानिया का सबसे अहम खनिज है। ट्रेन देश का आधे निर्यात के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश लोग समूह में सफर के दौरान खाना बनाने का सामान तक लेकर साथ चलते हैं। इतना ही नहीं खुले डिब्बे में ही खाना बनाते हैं। डिब्बे के एक ओर आग जलाने की व्यवस्था करते हैं और दूसरे ओर रेत की बोरियां लगाकर टायलेट बना लेते हैं। सफर के दौरान यात्रियों को सबसे कठिन चुनौती उठाने वाली धूल और लोहे के खनिज के कण होते हैं, जो आंख में चले जाते हैं। ट्रेन की आवाज में सोना तब बिल्कुल भूल जाईये है। ऐसा खास तौर से जाते समय होता जब डिब्बे खाली होते हैं और ट्रेन तेज चलती है इससे धूल ज्यादा आती है डिब्बे भी ज्यादा ही हिलते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह सफर उनके काम का हिस्सा है और वे हर महीने कई बार इसका सफर करते हैं। फिर भी वे इस सफर को हर बार पूरे जोश और उत्साह के साथ रोमांचक बना देते हैं।



काललंपुर में सुल्तान ऑफ जोहर इब्राहिम इस्कांदर मलेशिया के 17 वें किंग की शपथ लेते हुए।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का राजनीतिक करियर किया खत्म!

तोशाखाना मामले में मिया-बीबी को दी 14 साल की जेल सहित ये सजा

न्यूयार्क (एजेंसी)। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने बुधवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तानी समाचार आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दंपति को 10 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है और उन पर 787 मिलियन पीकेआर का जुर्माना लगाया गया है। यह एक दिन बाद आया है, जब पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को राज्य की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आया है। इस साल जनवरी में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के



तहत गठित पाकिस्तान की विशेष अदालत द्वारा इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को राज्य की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आया है। इस साल जनवरी में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के

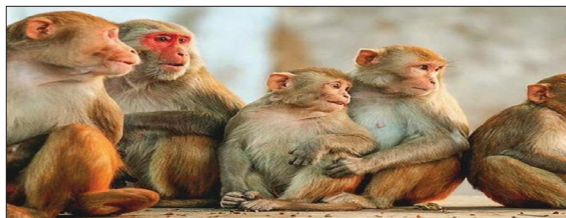
पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया था। मामले की सुनवाई रविवार पंडी की अदालत जेल में हुई, जहां खान को कैद में रखा गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मामला पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर किया गया था।

तोशाखाना मामला इस आरोप से संबंधित है कि इमरान खान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए 19 मिलियन पाउंड या 24,08,06,950 डॉलर जमा करने में विफल रहे। उन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्शन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 460 अरब रुपये के जुर्माने के खिलाफ उक्त राशि को आंशिक रूप से समायोजित करने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी। इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा, प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज हुसैन, अकबरे बेटेरियाज आलिया, इमरान खान के पूर्व सहयोगी शहजाद अकबर और जूलिफकार बुखारी के साथ-साथ बीबी की दोस्त फराह गोगी और वकील जिया मुस्ताफा भी इस मामले में सह-आरोपी हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने निक्की हेली पर युद्ध समर्थक होने का आरोप लगाया

वॉशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी की नेता एवं पार्टी की राष्ट्रपति पद की दायदारी की दौड़ में शामिल होने वाली भारतीय-अमेरिकी निक्की हेली पर अपना हमला तेज कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम ने हेली पर युद्ध समर्थक होने का भी आरोप लगाया है। वहीं, हेली ने ट्रंप पर निशाना साधकर 'अमेरिका को फिर से सामान्य बनाएं' का नया नारा गढ़ दिया। ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम के प्रवक्ता स्टीवन चेम्ग ने कहा, तथ्य यह है कि हेली को पता है कि उनके पास इस बात के लिए कोई ठोस तर्क या कोई युद्ध कारण नहीं है कि उन्हें राष्ट्रपति क्यों बना चाहिए। लेकिन मतदाता यह जानते हैं कि वह एक युद्ध समर्थक हैं, जो अमेरिका को अतर्हीन युद्धों में झोकना पसंद करेगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आशय और न्यू हैम्पशायर में पहली दो रिपब्लिकन प्राइमरी जीत ली है और दक्षिण कैरोलाइना में 30 प्रतिशत से अधिक अंकों से आगे हैं, जहां 23 फरवरी को प्राइमरी चुनाव होगा है। दक्षिण कैरोलाइना से दो बार की गवर्नर हेली (51) की लोकप्रियता उनके गृह राज्य में धीरे-धीरे बढ़ रही है जहां उन्हें काफी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

बंदरों के आतंक से परेशान नेपाल संसदीय समिति करेगी भारत का दौरा



काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल में 'बंदरों के आतंक' के बारे में चिंताएं व्यक्त करने के बाद नेपाली सांसदों और डॉक्टरों की एक टीम बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा करेगी। मॉडिया की एक खबर में बुधवार को यह बात कही गई। 'माइ रिपब्लिक' समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार इस दौर से पहले कृषि, सहकारी और प्राकृतिक संसाधन समिति के सदस्यों ने संसदीय बैठकों में 'बंदरों के आतंक' के मुद्दे को उठया और नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसमें कहा गया कि भारत सरकार इस यात्रा में सहायता करेगी। दस पशु चिकित्सकों और पांच वन रंजर के साथ, समिति बर्धियाकरण के

माध्यम से बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने संबंधी अध्ययन के लिए हिमाचल प्रदेश की यात्रा करेगी। वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार बंदरों को एक साल के लिए 'नाशक जीव' घोषित किया, जिससे इस दौरान बंदरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें मारने की अनुमति मिल गई। सरकार ने 2021 तक कम से कम चार बार अनुमति की समय सीमा बढ़ाई। खबर में कहा गया है कि नेपाली प्रतिनिधि सभा की एक अन्य समिति के सदस्य संसदीय संवाद और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को भारत पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति के सदस्य सात फरवरी को नेपाल लौटेंगे। 11 सदस्यीय इस समिति में आठ सांसद हैं।

अमेरिका में बढ़ रहे हैं नास्तिक, नहीं मानते किसी भगवान को

वॉशिंगटन (एजेंसी)। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में अमेरिका के 28 फीसदी लोगों ने खुद को किसी धर्म से जुड़ा नहीं बताया और नन की कैटेगरी सिलेक्ट की। इस कैटेगरी में नास्तिक (जो किसी भगवान को नहीं मानते) और अज्ञेयवादी या एनोस्टिक्स (ऐसे लोग जिनका किसी एक धर्म या भगवान पर भरोसा नहीं है) शामिल हैं। मतलब है कि अमेरिका की एक चौथाई से ज्यादा आबादी किसी धर्म को नहीं मानती। पिछले दो दशक में किसी धर्म को न मानने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। 24 जनवरी को जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 28 फीसदी आबादी किसी धर्म को नहीं मानती। जबकि 1990 में हुए सर्वे में 90 फीसदी लोग इसी धर्म को मानते थे।



अनोस्टिक्स और 63 फीसदी ने कहा कि उनका किसी एक चीज पर भरोसा नहीं है। एक तरीके से कुल 19 फीसदी लोग ऐसे हैं जो किसी भगवान या किसी अर्थात् ऊर्जा को नहीं मानते। वह इस बात में भरोसा भी नहीं करते कि ईसान की कोई आत्मा जैसी चीज होती है और इस दुनिया से अलग भी स्वर्ग-नर्क जैसी कोई चीज है। तो किसी धर्म को न मानने की क्या वजह है? प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक जिन लोगों ने खुद को कोई धर्म न मानने वाला बताया, उनमें से 43 फीसदी लोगों ने कहा कि धर्म समाज को

फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि 14 फीसदी लोगों ने कहा कि यह समाज के लिए अच्छा है। इसी तरह 41 फीसदी लोगों ने कहा कि धर्म, अच्छे और बुरा दोनों है। अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में किसी धर्म को न मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोग नास्तिक हैं। इसके अलावा चीन, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और

चेक रिपब्लिक भी टॉप 10 नास्तिक देशों में शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 75 करोड़ लोग नास्तिक हैं। किसी धर्म को न मानने की जो तीन सबसे बड़ी वजहें निकलकर सामने आईं, उनमें से सबसे पहला है-धार्मिक शिक्षा पर सवाल। दूसरा-धार्मिक संगठनों के प्रति नफरत और तीसरा जीवन में धर्म की आवश्यकता। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 28 फीसदी लोगों ने खुद को किसी धर्म से जुड़ा नहीं बताया, वे धार्मिक अमेरिकी लोगों के मुकाबले कम पढ़े लिखे हैं। हालांकि आवरऑल आंकड़े देखें तो इन 28 फीसदी में से जो लोग नास्तिक और एनोस्टिक्स हैं, उन्होंने कम से कम उच्च शिक्षा हासिल की है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण बढ़ा है, इसका व्यक्तिगत असर और नापसंद पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसने लोगों की पारंपरिक मान्यताओं, धार्मिक संगठनों पर विश्वास और भरोसे को कम किया है।

राष्ट्रपति अल्वी ने खोली पाकिस्तान की दुर्दशा की पोल, कहा-देश में तुरंत लागू हो 'शिक्षा आपातकाल'

इस्लामाबाद। (एजेंसी)। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने देश के लगातार बिगड़ते हालात को खुद ही पोल खोल दी है। अल्वी ने पाकिस्तान में नाकाम शिक्षा नीतियों की जमकर ध्वज्या उड़ाई और सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए आधिकारिक तौर पर देश में 'शिक्षा आपातकाल' की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल से लेकर बढ़ते कर्ज, आतंकवाद, चल रही सांप्रदायिक हिंसा और सामाजिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हुए, पाकिस्तान निम्न स्तर के शिक्षा मानकों की अतिरिक्त दुर्दशा का सामना कर रहा है। उन्होंने जनवरी 2024 में विश्व शिक्षा दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में लगभग 26 मिलियन स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन की वकालत की। राष्ट्रपति अल्वी ने स्कूलों की भारी कमी को रेखांकित किया, लगभग

50,000 शैक्षणिक संस्थानों की कमी का अनुमान लगाया, इस कमी के लिए शिक्षा के लिए धन के अल्प आवंटन को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति अल्वी की चिंताओं के अनुरूप, संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यवाहक मंत्री, मदद अली सिंधी ने अपर्याप्त शिक्षा के परिणामों को सामाजिक पिछड़ेपन के मूल कारण के रूप में रेखांकित किया, जो गरीबी, अपराध, हिंसा और आतंकवाद के ऊंचे स्तर में योगदान देता है। बता दें कि समकालीन संदर्भ में, पाकिस्तान गरीबी, असुरक्षा, सांप्रदायिकता और आतंकवाद सहित असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों की उत्पत्ति अपर्याप्त असाक्षरता, सीमित सार्वजनिक जागरूकता और एक अप्रभावी शिक्षा प्रणाली द्वारा काम चलायक निष्कर्षता से होती है। दुर्भाग्य से, पाकिस्तान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार नजरअंदाज किया गया है, जिसके

परिणामस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं में अविकसितता हुई है। शिक्षा, जिसे एक उच्च शिक्षा क्षेत्र माना जाता है, पाकिस्तान की स्थापना के बाद से इस क्षेत्र को आविर्त अल्प बजट से स्पष्ट है। इस अपर्याप्त वित्तीय सहायता ने शैक्षणिक गुणवत्ता की नींव को कमजोर कर दिया है, जिससे एक ऐसी प्रणाली तैयार हो गई है जो देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने में विफल रही है। आधी सदी से अधिक समय बीतने और 25 से अधिक शैक्षणिक नीतियों को अपनाते के बावजूद, शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के सामने बढ़ती आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का अपर्याप्त समाधान करती है। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली चुनौतियां कई प्रकार की हैं, जिनमें अपर्याप्त बजटीय आवंटन, नीति कार्यान्वयन पर खासियां, एक नुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, घटिया शिक्षक गुणवत्ता,



उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन, लक्ष्यहीन शैक्षणिक दृष्टिकोण, कम नामांकन दर, बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट, राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। एक नुटता की इस कमी ने सामाजिक सुशोकाण खासियां, एक नुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, घटिया शिक्षक गुणवत्ता,

उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन, लक्ष्यहीन शैक्षणिक दृष्टिकोण, कम नामांकन दर, बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट, राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। एक नुटता की इस कमी ने सामाजिक सुशोकाण खासियां, एक नुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, घटिया शिक्षक गुणवत्ता,

उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन, लक्ष्यहीन शैक्षणिक दृष्टिकोण, कम नामांकन दर, बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट, राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। एक नुटता की इस कमी ने सामाजिक सुशोकाण खासियां, एक नुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, घटिया शिक्षक गुणवत्ता,

एच-1बी वीजा के लिए अमेरिकी प्रशासन ने किए बड़े बदलाव

वॉशिंगटन। अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वीजा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया छह मार्च से शुरू होगी। एक अमेरिकी संघीय एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। नई व्यवस्था के तहत कई तरह के प्रावधान किए हैं, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा पंजीकरण के लिए लाभार्थी-केंद्रित चयन प्रक्रिया का प्रावधान भी शामिल है। अतीत में अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक बार आवेदन किए जाने पर व्यवस्था में हेराफेरी की आशंका रहती थी, लेकिन एच-1बी वीजा के लिए आवेदन अब व्यक्तिगत आवेदकों के आधार पर गिने और स्वीकार किए जाएंगे। यहां तक कि अगर एक व्यक्ति विभिन्न कंपनी के लिए कई आवेदन जमा करता है, तब उन्हें पासपोर्ट नंबर जैसे व्यक्तिगत परिचय पत्र के आधार पर एक आवेदन के रूप में गिना जाएगा। अमेरिकी नागरिकता और आरजन सेवा (यूएससीआईएस) ने भी नए नियमों की घोषणा की है, जिसका मकसद एच-1बी पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना और हेराफेरी की संभावना को कम करना है। संघीय एजेंसी ने कहा कि नयी व्यवस्था से पंजीकरण प्रणाली में हेराफेरी की आशंका कम रहेगी और यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को चयनित होने का समान अवसर मिले।

कोकीन निर्यात के मामले में ब्रिटिश-भारतीय जोड़े को 33 साल की जेल

—मनी लॉन्ड्रिंग सहित ऑस्ट्रेलिया को आधा टन कोकीन निर्यात का लगा था आरोप

लंदन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया को कोकीन निर्यात के मामले में आरोप सिद्ध होने पर ब्रिटिश-भारतीय जोड़े को 33 साल की जेल हुई है। जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के एक जोड़े ने आधा टन से अधिक कोकीन निर्यात की थी। इसके साथ ही मनी ग के भी आरोप लगे हैं। 59 वर्षीय अरती धीर और 35 वर्षीय कवलजीतसिंह रायजान, जिन्होंने कोकीन निर्यात के 12 मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामलों में दोषी ठहराया गया था। साइबरवार्क क्राउन कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान, अभियोजक ह्यू फ्रेंच ने दंपति की कार्यप्रणाली की तुलना अपराध नाटक ओजार्क और ब्रेकिंग बैंड से की। फ्रेंच ने निर्दयी और लालची जोड़े को ऑसत विवाहित जोड़े से बहुत अलग बताया है। मॉडिया में आई खबरों के अनुसार यह 25 साल की उम्र का अंतर नहीं है, जो अलग है, यह तथ्य है कि वे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की दुनिया में काम करते थे। मई 2021 में सिडनी पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल द्वारा कोकीन पकड़े जाने के बाद

राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के जांचकर्ताओं ने धीरे धीरे रायजाना की पहचान की थी। धातु के छह टूलबॉक्स में 514 किलो कोकीन मिली थी। अधिकारियों को पता चला कि यह खेप धीरे धीरे रायजाना के पास थी, जिन्होंने इसकी तस्करी के एकमात्र उद्देश्य के लिए विप्लाई फ्रेट सर्विसेज नामक कंपनी बनाई थी। एनसीए ने जारी एक बयान में कहा कि दोनों प्रतिवादी जून 2015 में कंपनी के गठन के बाद से अलग-अलग समय पर कंपनी के निदेशक रहे हैं। जब्त की गई ड्रग्स वाले धातु टूलबॉक्स के प्लास्टिक पैकिंग पर रायजाना की उंगलियों के निशान पाए गए, जबकि 2855 पाउंड मूल्य के टूलबॉक्स के ऑर्डर की रसीदें दंपति के घर से मिलीं। एनसीए ने दावा किया कि जून 2019 से ऑस्ट्रेलिया को 37 खेप भेजी गई हैं, इनमें से 22 नकली रन थीं और 15 में कोकीन थे। अपराध एजेंसी के अनुसार, हवाई अड्डे की माल डुलाई प्रक्रियाओं के बारे में अपनी जानकारी का दोनों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया। एनसीए के वरिष्ठ जांच अधिकारी गियर्स फिलिप्स ने कहा कि अरती धीर और कवलजीतसिंह रायजाना ने यूके से ऑस्ट्रेलिया तक लाखों पाउंड मूल्य की कोकीन की तस्करी के लिए हवाई माल डुलाई का इस्तेमाल किया।

भाजपा का आरोप, ईडी को डराने के लिए लालू परिवार ने जुटाई भीड़

पटना । भाजपा ने आरोप लगाया है कि लालू और उसके परिवार ने ईडी के अफसरों को डराने के लिए भीड़ जुटाई थी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले लोगों की कीमती जमीन लिखवाने के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ के दौरान ईडी पर दबाव बनाने और अफसरों को डराने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटाना राजद के अपराधिक चित्र का सूचक है। सुशील मोदी ने अपना बयान जारी कर कहा कि ईडी पर दबाव बनाने और अफसरों को डराने के लिए अपनाये जा रहे हथकड़ों से न तो जांच रुकेगी और न लालू परिवार दोषमुक्त हो पाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लेने तथा मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिलने पर सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया। इस आधार पर प्रवर्तन ईडी पिछले साल से लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पटना में लालू यादव और तेजस्वी से पूछताछ भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। भाजपा सांसद मोदी ने कहा कि 10 मार्च 2023 को दिल्ली-पटना में लालू परिवार के विभिन्न परिवारों पर छापा मारा गया और एक करोड़ रुपए नकद तथा 1.25 करोड़ रुपए के कीमती सामान जब्त किए गए थे। ईडी ने उसी समय छह करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मकान, घरेलू और दिल्ली का बंगला भी जब्त किया था। 11 नवम्बर 2023 को लालू परिवार के लिए काम करने वाली फर्नीचर कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स और एबी एक्सपोर्ट्स के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई। वह अब भी न्यायिक हिरासत में है। सांसद मोदी ने कहा कि एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद से लालू परिवार पर कानून का शिकंजा कसता गया। भाजपा सांसद ने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना होगा कि वे दिल्ली में 150 करोड़ के मकान डी-1088 के मालिक कैसे बन गए।

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

जीद । एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में एक व्यक्ति को जीद की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 7मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रशहा की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त प्रदीप को बीस साल के कारावास की सजा सुनायी और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में अभियुक्त को दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2023 को पुलिस में रिपोर्ट की थी की 16 मार्च को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब है। उस दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राम कालोनी के प्रदीप ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने गायब लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा पोक्सो कानून की धाराएं भी लगाई थीं, तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।

लेह लद्दाख में चरवाहों ने चीनी सैनिकों को दिखाई आंख, यह भारत की भूमि

-चुशुल के पार्षद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली । लेह लद्दाख के सुदूर पर्वतीय इलाके में फिर से चीनी सेना की नापाक हरकत सामने आई है। लद्दाख में चरवाहों के एक समूह ने चीनी सैनिकों का तब सामना किया जब उन्होंने भारत-चीन सीमा के पास स्थानीय लोगों को भेड़ चराने से रोकने की कोशिश की। चरवाहे, जिन्होंने 2020 के कानवान संघर्ष के बाद क्षेत्र में जानवरों को चराना बंद कर दिया था, अब क्षेत्र में लौट आए हैं लेकिन चीनी सेना ने उन्हें रोक दिया है। इस बात से घबराए बिना, लोगों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के सदस्यों से सवाल कर कहा कि वे भारतीय क्षेत्र में थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है, जिसमें कई लोगों ने चरवाहों की बहादुरी पर टिप्पणी की है। वीडियो साझा कर, चुशुल के पार्षद कोचोक स्टेनजिन ने कहा कि वह खानाबदोशों को सलाम करते हैं। जो हमेशा हमारी भूमि की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं और राष्ट्र की दूसरी संरक्षक शक्ति के रूप में खड़े होते हैं। स्टेनजिन ने कहा कि देखिए कैसे हमारे लोग पीएलए के सामने अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र को वे रोक रहे हैं, वह हमारे खानाबदोशों की चरगागाह भूमि है। पीएलए हमारे खानाबदोशों को हमारे क्षेत्र में चराने से रोक रही है। ऐसा लगता है कि विभिन्न कारणों से यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है धारणाओं की रेखाएँ। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि चरवाहों का सेना के सामने खड़ा होना यह देखकर खुशी होती है।

टीपू सुल्तान की मूर्ति पर जूतों की माला, कर्नाटक शहर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन

बैंगलोर । कर्नाटक के रायचूर जिले में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया, जब मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर को जूते की माला पहनाई गई। मुस्लिम समुदाय ने यातायात अवरुद्ध कर भारी विरोध प्रदर्शन किया और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सिरवार कस्बे में टायरों में भी आग लगा दी। बाद में चित्र से माला हटा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आधासन दिया है कि वह 24 घंटे के भीतर बदमाशों को गिरफ्तार कर लेंगे। इस आधासन के बाद धरना वापस ले लिया गया है। रायचूर के सिरवार पुलिस स्टेशन में एक आईआर दर्ज की गई है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। पिछले साल दिसंबर में टीपू सुल्तान के नाम पर मैसूर हवाई अड्डे का नाम बदलने के कांग्रेस विधायक प्रसाद अब्दुल्ला के प्रस्ताव की कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तीखी आलोचना की थी। हबली-धारावाड़ (पूर्व) विधायक का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे के नाम बदलने के लिए केंद्र को पत्र लिखने पर चर्चा के दौरान आया। चित्र के दौरान अब्दुल्ला ने कहा मैं मैसूर हवाईअड्डे का नाम बदलकर टीपू सुल्तान हवाईअड्डा करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे बीजेपी और बीजेपी विधायकों में हंगामा मच गया। 18वीं सदी के शासक कई वर्षों से कांग्रेस और भाजपा के बीच वाक्ययुद्ध के केंद्र में रहे हैं। मुस्लिम शासक को लेकर विवाद पहली बार 2016 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन सिद्धारमेया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 10 नवंबर को उनके जन्मदिन को 'टीपू जयंती' के रूप में मनाना शुरू किया। हालाँकि, भाजपा ने इस कदम का विरोध किया और 2019 में राज्य में सत्ता में आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

कुल्लू-मनाली में सीजन का पहला स्नोफॉल, खुशगवार हुआ मौसम

- भारी बर्फबारी में अटल टनल के आसपास फंसे 300 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला

शिमला । कुल्लू-मनाली में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। हालांकि लोग यहां पर लंबे समय से बर्फबारी-बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब लैंकन हिमालय प्रदेश के टूरिस्टों के लिए यह खुशखबरी है। प्रदेश भर में मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पॉटि, उलहोत्री, पांगी, भरमौर सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। साथ ही मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में बारिश हुई है। इस दौरान लाहौल स्पॉटि में अटल टनल सहित अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट फंसे गए थे, जिन्हें कुल्लू और लाहौल पुलिस ने सुरक्षित निकाला है। फिलहाल, बुधवार को प्रदेश के मंडी, कुल्लू, मनाली सहित ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, कुल्लू पुलिस ने अटल टनल रोहतांग से सोलंगनाला तक 300 पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर मनाली पहुंचाया है। एसडीएम रमन शर्मा ने एसएचओ तहसीलदार और लोकल लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया है। एसडीएम रमन शर्मा ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के आसपास भारी बर्फबारी में फंसे 50 पर्यटक वाहनों और एचआरटीसी बस मे करीब 300 पर्यटकों को प्रशासन की टीम ने सकुशल 7ल मनाली पहुंचाया। एसडीएम रमन शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी टूरिस्ट सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। ड़धर बर्फबारी का इंतजार कर रही मनाली की पब्लिक के लिए भी खुशखबरी है। मनाली शहर में सीजन का पहला हिमपात देर रात हुआ। यहां मंगलवार देर शाम पहले बारिश हुई और फिर बर्फबारी भी हुई। बर्फबारी के चलते मनाली में पर्यटन कारोबारी और किसान-बागवानों के चेहरे खिल गए हैं।

मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, यह धार्मिक स्थल है : उच्च न्यायालय

-तमिलनाडु के मंदिरों में हाई कोर्ट ने लगाई गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, बल्कि यह धार्मिक स्थल है। मंगलवार को हाई कोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। जिसमें कहा गया हो कि गैर-हिंदुओं को कोडिमारम (ध्वजपोल) क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। उन घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए जहां गैर-हिंदुओं ने कथित तौर पर गैर-धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंदिरों में प्रवेश किया, मद्रास हाई कोर्ट की मुदुरै पीठ के न्यायमूर्ति एस श्रीमथी ने कहा, मंदिर कोई पिकनिक या पर्यटन स्थल नहीं है। कोर्ट के इस फैसले में बिना किसी हस्तक्षेप के अपने धर्म का पालन करने के हिंदुओं के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया। यह निर्णय डी सेंथिलकुमार द्वारा दायर एक याचिका के दौरान आया, जिन्होंने डिंडीपुल जिले के पलानी में अरुलमिप्पु पलानी धनदायुथपानी स्वामी मंदिर और उसके उम-



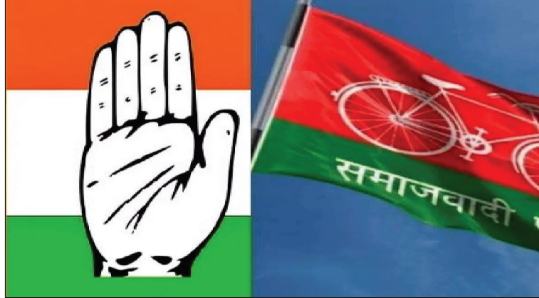
मंदिरों में अकेले हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने मंदिर के प्रवेश द्वारों, ध्वजस्तंभ के पास और अन्य प्रमुख स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, जो कोडिमारम से परे गैर-हिंदुओं पर प्रतिबंध का संकेत देते हों। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई गैर-हिंदू किसी विशिष्ट देवता के दर्शन करना चाहता है, तो उन्हें हिंदू धर्म में अपनी आस्था और मंदिर के रीति-रिवाजों का पालन करने की इच्छा की पुष्टि करने वाला एक वचन पत्र देना होगा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि वे उन गैर-हिंदुओं को अनुमति न दें जो हिंदू धर्म में विश्वास

नहीं करते हैं। यदि कोई गैर-हिंदू मंदिर में किसी विशेष देवता के दर्शन करने का दावा करता है, तो उत्तरदाताओं को उक्त गैर-हिंदू से एक वचन लेना होगा कि वह देवता में आस्था है, और वह हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेगा और मंदिर के रीति-रिवाजों का भी पालन करेगा और इस तरह के उपक्रम पर उक्त गैर-हिंदू को मंदिर में जाने की अनुमति दी जा सकती है। इतना ही नहीं अदालत ने मंदिर प्रशासन को रीति-रिवाजों, प्रथाओं और आगमों को सख्ती से बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने आदेश को पलानी मंदिर तक सीमित रखने की उत्तरदाताओं को याचिका को खारिज कर दिया, और कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव और शांति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश सभी हिंदू मंदिरों पर लागू होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और यह सभी हिंदू मंदिरों पर लागू होना चाहिए, इसलिए उत्तरदाताओं की याचिका खारिज कर दी जाती है। इसलिए, राज्य सरकार, मानव संसाधन और सीई विभाग, मंदिर प्रशासन में शामिल सभी व्यक्तियों को सभी हिंदू मंदिरों के लिए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

यूपी में इंडिया गठबंधन में राउ, सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच दिखी तानातनी

-सपा की 11 सीटों को कांग्रेस ने बताया हास्यास्पद

लखनऊ (एजेंसी)। पीएम मोदी को सत्ता से हटने के लिए बना इंडिया गठबंधन में इनादियों सबकुछ ठीक नहीं है। इस कारण है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तानातनी देखने को मिल रही है। सपा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 11 सीटें देने और 16 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर कांग्रेस ने अपनी नाजुगी जाहिर की है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, हम सभी को पहले एक आम सहमत पर आना होगा, इस बात पर आम सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें कैसे हराएंगे, इसके लिए हम सभी को सहमत होना होगा चाहे वह किसी भी मामले में हों। हमें समय-



समय पर समन्वय बनाते रहना होगा।

कांग्रेस नेता पांडे ने कहा कि अगर सपा कहती है कि उन्होंने कांग्रेस को सीटें दीं तब यह हास्यास्पद है। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ समझौता कर रही है, तब हमारी भी अपनी एक पहचान है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी किसी को इसकी कमी लगती है, तब मैं समझता हूँ कि उसे गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, कभी-कभी

इसमें कुछ हिलाई भी आई होगी, लेकिन आने वाले सालों में आप इस एक बड़ी ताकत के रूप में उभरता हुआ देख सकते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सपा या कोई अन्य पार्टी कहती है कि उन्होंने कांग्रेस को सीटें दीं हैं, तब मुझे नहीं पता कि मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, ये अपने आप में हास्यास्पद बातें हैं। कोई भी एकतरफा फैसला नहीं होता है, गठबंधन में शामिल सभी लोग एक साथ आते हैं और सर्वसम्मति से उस बात की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे मन में समाजवादी पार्टी के प्रति पूरा सम्मान है और बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है, लेकिन इस तरह के ट्वीट या ऐसी खबरें या प्रेस में दी जा रही ऐसी बातें निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। पांडे ने कहा कि अगर यह खुलेआम दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का पालन नहीं कर रही है, तब ऐसा ही है।

ईडी ने पांचवी बार 2 फरवरी को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाला केस में फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांचवीं बार समन जारी कर 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने को कहा है। इसके पहले ईडी ने चार समन जारी कर चुकी हैं। चारों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके पहले दिल्ली शराब कांड में केजरीवाल को चौथे समन के तहत ईडी ने 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। केजरीवाल को तीसरा समन 3 जनवरी को दिया गया था। वहीं, पिछले साल दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था। चारों समन में वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

ममता ने कांग्रेस पर लगाया भाजपा की मदद का आरोप, बोलीं- एक भी सीट साझा नहीं करेंगे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए तुणमूल कांग्रेस नेतृत्व को मनाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिशों के बीच, ममता बनर्जी ने बुधवार को महिक्कानुंन खडगे के नेतृत्व वाली पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि सीपीआई (एम) के साथ उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत करेगा। एक टिप्पणी में, जिसने वास्तव में राज्य में इंडिया गुट को खत्म करने का आह्वान किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनकी दो सीटों को पेशकश को अस्वीकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के पास राज्य विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। मैंने उन्हें दो लोकसभा सीटों की पेशकश की, दोनों मालदा में, लेकिन वे और अधिक चाहते थे। इसलिए, मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ एक भी सीट साझा नहीं करूँगी। सीपीआई (एम) उनकी नेता है... क्या वे सीपीआई (एम) की

यातनाओं को भूल गए हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि वह वाम दल को कभी माफ नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों पर अत्याचार किया है। तुणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मैं सीपीआई (एम) को कभी माफ नहीं करूँगा।' मैं उन लोगों को भी माफ नहीं करूँगा जो सीपीआई (एम) का समर्थन करते हैं... क्योंकि ऐसा करके वे वास्तव में भाजपा का समर्थन करते हैं। पिछले पंचायत चुनाव में मैंने देखा है। बनर्जी ने कहा कि अगर मालदा से कांग्रेस के पूर्व दिग्गज दिवंगत गनी खान चौधरी के परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो उन्हें 'कोई आपत्ति नहीं' है। उन्होंने कहा कि वे (कांग्रेस) भाजपा को मजबूत करने के लिए सीपीआई (एम) के साथ मिलकर लड़ेंगे... केवल टीएमपी ही शक्ति में भाजपा से राजनीतिक रूप से लड़ने में सक्षम है।

रामलला के खिलाफ अनशन, सुरन्या अय्यर के खिलाफ सोसायटी का एक्शन, मांफी मांगे या सोसायटी छोड़ दें

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के खिलाफमें बयानबाजी करना और अनशन रखना कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी को महंगा साबित हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर जिस सोसायटी में रहती हैं, वहां से उन्हें निकलने को कहा गया है। दरअसल, कांग्रेस नेता की बेटी सुरन्या ने राम मंदिर निर्माण और रामलला को प्राण प्रतिष्ठ के विरोध में तीन दिनों का अनशन किया था। आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था।

इसकारण सुरन्या के खिलाफ उनकी सोसायटी की आरडब्ल्यूए ने एक्शन लिया है। आरडब्ल्यूए ने नोटिस जारी कर मणिशंकर और उनकी बेटी सुरन्या को पत्र लिखकर माफ़े मांगने को कहा है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि दोनों या सार्वजनिक रूप से माफ़े मांगेंजहीं सोसायटी छोड़कर चले जाएं। दरअसल, मणिशंकर अय्यर की बेटी दिल्ली के जंपपुरा इलाके में रहती हैं। सोसायटी के एक्शन पर सुरन्या ने फेसबुक पर अपना बयान जारी कर कहा, यह बयान भरे फास्ट



के बारे में एक टेलीविजन कहानी के संबंध में है। सबसे पहले संबंधित रजिस्ट्रार वेलफेयर एसोसिएशन जिस कॉलोनी से है, वहां में रहती ही नहीं हूँ। दूसरा, मैं फिलहाल मीडिया से बात न करने का फैसला किया है, क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप मुझे जानते हैं। मैं भारत में अब तक अपनी सारी उम (लगभग 50 वर्ष) के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूँ, पढ़ी हूँ, काम किया। फिलहाल मैं अपनी बातें अपने फेसबुक और यू-ट्यूब

पेजों पर ही छोड़ूंगी ताकि आप स्वयं, शांति से, इसके बारे में सोच सकें। आइए हम गाली-गलौच के बजाय, कुछ सोचने का प्रयास करें, जय हिन्द ! दरअसल, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठ हो रही थी, तब मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या ने अनशन किया था। इसकी वजह से सोसायटी के लोग नाजुब दिख रहे थे। सुरन्या ने कहा था कि उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनशन किया था। इसके बाद से ही सोसायटी के लोग उनके खिलाफएक्शन की मांग कर रहे थे।

बीते 12 वर्षों में जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी रही दिल्ली, उत्तर भारत में घना कोहरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लोगों को ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का कहर भी झेलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्वआई) भी 350 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह जनवरी 12 साल में सबसे ठंडी है। आईएमडी का अनुमान है कि मंगलवार को मौसम की स्थिति खराब रहेगी, बुधवार और गुरुवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम की मौजूदा खराबी के कारण रेल और उड़ान संचालन में देरी हो रही है, जबकि घने कोहरे के कारण खराब दृश्यता के कारण सुबह और रात के दौरान सड़क यात्रा को असुरक्षित माना गया है।

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भीषण कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है और परिवहन बाधित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में बहुत घने कोहरे की

सूचना दी है, जिसमें गंगानगर में केवल 25 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में, कोहरे की मोटी परत ने शहर को ढक लिया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और आईएमडी को कुछ क्षेत्रों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी करना पड़ा। न्यूनतम तापमान 6।8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में पालम और सफदरजंग जैसे प्रमुख स्थानों पर दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जहां मध्यम से हल्का कोहरा छाया रहा।

स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए, आईएमडी ने 31 जनवरी और 1 फरवरी दोनों को दिल्ली में हल्की बारिश की आशंका जवाब है, क्योंकि दूसरा पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त, 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की संभावना है, जिससे उत्तरी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होगी, खासकर 30 और 31 जनवरी को। 3

फरवरी तक जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और हिमाचल प्रदेश सहित क्षेत्रों में मध्यम बारिश या बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। विशेष रूप से, 30 और 31 जनवरी को कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी की उम्मीद है, हिमाचल के लिए भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। 31 जनवरी को प्रदेश। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्लीवासियों की मंगलवार को सुबह घने कोहरे और सर्द सुबह के साथ हुई और न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के पूर्वानुमान से पता चला है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि कोहरे के कारण सुबह साढ़े पांच बजे पालम और सफदरजंग में दृश्यता कम होकर 50 मीटर रह



गई, इससे उड़ान और ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने मंगलवार सुबह 6 बजे यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। मौसम विज्ञानी ने कहा, सुबह 9 बजे, पालम और सफदरजंग में दृश्यता लगातार 50 मीटर तक कम हो गई। इसके अलावा, शहर भर के कई स्टेशनों पर हवा

की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आनंद विहार क्षेत्र में सुबह 9 बजे पीएम2.5 का स्तर 355 पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया और पीएम10 233 या खराब पर पहुंच गया।

सूरत हवाई अड्डे को सरकारी राजपत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया

केंद्र ने सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, गुजरात को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

गुजरात को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया है। सूरत हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं, अब

सरकारी गजट में सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। इससे पहले कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वर्तमान में धोलेरा में एक और

धोलेरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन रहा है

सूरत से पहले गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा राजकोट में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। वर्तमान में धोलेरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि १७ दिसंबर २०२३ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बर्स और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने सूरत आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सूरत की जनता और यहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों को दो और सौगातें मिली हैं। डायमंड बर्स के साथ सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है और दूसरी बड़ी बात ये है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है।

इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से उद्योगपतियों और

हीरा व्यापारियों को काफी फायदा होगा। सूरत के लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पाकर खुश हैं। सूरत एयरपोर्ट से दुबई और शारजाह के लिए उड़ानें शुरू की गई हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में सूरत एयरपोर्ट से अन्य देशों के लिए भी उड़ानें खाना होंगी।



दक्षिण जोन-बी (कनकपुर) के मूल्यांकन एवं संग्रह

विभाग द्वारा सघन कर वसूली अभियान के तहत कार्रवाई

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

दक्षिण जोन-बी (कनकपुर) निर्धारण एवं संग्रहण विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है और जो संपत्ति मालिक अभी भी संपत्ति कर भुगतान में लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी संपत्तियों को सील करने और नल कनेक्शन, जल निकासी कनेक्शन काटने जैसी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तुरंत टैक्स जमा करने को कहा। आयुक्त एवं दिवस. आयुक्त श्री की तिथि. दिनांक ३०/०१/२०२४ को राजस्व बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुसार सूरत नगर निगम के



दक्षिण जोन-बी (कनकपुर) के कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग द्वारा सघन कर संग्रहण अभियान के तहत ऊज क्षेत्र के तस्लीम इंडस्ट्रियल, वी.एम. धामनवाला इ. और पी.एम. धामनवाला इ. क्षेत्र में कुल १०८ संपत्तियां बरामद की गई हैं, जिनमें से ६१ संपत्तियों को सील कर दिया गया है



और मौके पर २५,६२,३२९/- लाख की वसूली की गई है।

साथ ही अग्रिम चेक के रूप में १४,९७,५९२/- लाख रुपये लिये गये हैं। अतः जिन करदाताओं का संपत्ति कर बकाया है, उन्हें विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे सभी जोन कार्यालयों और नागरिक केंद्रों से संपर्क करें और तुरंत कर का भुगतान करें।



सूर्या मराठी गैंग के सदस्यों ने आधी रात को

युवक की हत्या कर दी

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के आठवें गेट के पास पिंडू नवसारीवाला को सरेआम हत्या कर दी गई। अनुमान है

कि सूर्या मराठी गिरोह के सदस्यों ने हत्याओं को अंजाम दिया है क्योंकि गैंग वोर फिर से सक्रिय हो गया है। धारदार हथियार के वार से ६ लोगों की मौत हो गई। उमरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आधी रात को हुई हत्या के संबंध में आगे की जांच कर रही है। घटना की सूचना देर रात उमरा पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सिविल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बी.एससी. नर्सिंग छात्राओं का शपथ समारोह

सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम हॉल में दीप प्रज्वलन समारोह और शपथ समारोह आयोजित

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत न्यू सिविल अस्पताल स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में १४वें बैच प्रथम वर्ष बीएससी नर्सिंग छात्रों का दीप प्रज्वलन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित दीप प्रज्वलन समारोह में नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. इंद्रावती राव एवं टी.बी. और चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉ. पास्त्र वडगामा ने बीएससी

नर्सिंग की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और शपथ दिलाई। नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. इंद्रावती राव ने नर्स के जीवन में दीप प्रज्वलन और शपथ का महत्व समझाते हुए कहा कि नर्सिंग के साथ मानव सेवा को जोड़कर नर्सिंग को नई पहचान देने वाले ई.एस. लैप लाइटनिंग और शपथ की अवधारणा १८२० में पैदा हुई फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ी हुई है। आधुनिक नर्सिंग की अग्रणी के रूप में उन्हें 'लेडी विद द लैंप' के नाम से जाना जाता है।

नर्स अस्पताल का दिल होती है, और कोई भी अस्पताल या डॉक्टर उनके बिना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। इस मौके पर नर्मद यूनिवर्सिटी नॉर्मिनी बोर्ड मेंबर डॉ. महेंद्रसिंह चौहान ने कहा, नर्सिंग एक नेक प्रोफेशन है, आजकल नर्सिंग को एक बेहतरीन करियर विकल्प माना जाता है। किसी डॉक्टर या अस्पताल की सफलता में नर्सिंग सेवाओं का अद्वितीय योगदान होता है। नर्स की भूमिका स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आधारशिला है। मरीज की देखभाल, सुख

और इलाज की जिम्मेदारी नर्स की होती है। नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़वाला ने कहा, पिछले दिसंबर में न्यू सिविल स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज के सात छात्रों को एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में चुना गया है, जो दक्षिण गुजरात के लिए एक गौरवपूर्ण घटना है। नर्सिंग छात्रों को कॉलेज की ओर से हर संभव मदद और समर्थन दिया जाता है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सूरत के विद्यार्थियों को कोर्स के बाद शत-प्रतिशत रोजगार मिलना यहां के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। इस अवसर पर सूरत नर्सिंग कॉलेज में ३३ साल की लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई प्रोफेसर किरण डोमडिया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

गौरतलब है कि नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद नर्सिंग प्रशिक्षु अस्पताल के वार्ड में जाते हैं और मरीजों की सेवा उपचार का व्यावहारिक और वास्तविक अभ्यास करने से पहले कर्तव्यनिष्ठा से मरीजों की सेवा करने की शपथ लेते हैं। जबकि प्रथम वर्ष के छात्र अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलन करके इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं।



चैंबर द्वारा म्यांमार, मिस्र और सैंटो डोमिंगो में भारत के राजदूतों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई

एसजीसीसीआई द्वारा मिशन ८४ के तहत ऑनलाइन बैठक

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट मिशन ८४ के तहत यांगोन म्यांमार, काइरो मिस्र और सैंटो डोमिंगो में भारतीय राजदूतों और वहां भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वधासिया ने एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट मिशन ८४ की बुनियादी जानकारी देते हुए कहा कि भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए मिशन ८४ के तहत एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया है, जिसके साथ ८४,००० उद्यमी-व्यापारी और भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से निर्यातकों, देशों में कारोबार करने वाले ८४,००० व्यवसायियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसी तरह भारत के ८४ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और दुनिया के विभिन्न ८४ देशों के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को भी इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए बैठकें हो रही हैं। म्यांमार के यांगून में भारतीय

दूतावास के द्वितीय सचिव अशोक कुमार ने कहा कि म्यांमार की ६० प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। म्यांमार का लुगदी उद्योग भारत से निर्यात पर निर्भर है। म्यांमार भारत से सबसे अधिक

कपड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, सौर और भवन निर्माण सामग्री निर्यात करने के विशाल अवसरों पर चर्चा की गई: चैंबर अध्यक्ष रमेश वधासिया

फार्मास्यूटिकल उत्पादों का आयात करता है। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, इसलिए उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में सूरत के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल को म्यांमार आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सूरत के व्यापारियों को मिस्र के काहिरा में भारतीय

दूतावास के द्वितीय सचिव (वाणिज्य) राव प्रवीण सिंह ने कहा कि मिस्र में कपड़ा क्षेत्र के साथ-साथ सूती और सिंथेटिक वस्त्रों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निर्यात के कई अवसर

हैं। उन्होंने मिस्र में भारत से कौन-कौन से उत्पाद आयात किये जाते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूरत के उद्यमी मिस्र में कपड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और सोलर जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पाद निर्यात कर सकते हैं। उन्होंने सूरत के व्यापारियों को मिस्र में चैंबर ऑफ कॉमर्स

के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में सूरत के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मिस्र आने के लिए आमंत्रित किया। सैंटो डोमिंगो में भारत के राजदूत रामजी अब्बागानी ने कहा कि सूरत के व्यापारियों के लिए सैंटो डोमिंगो को विभिन्न उत्पाद निर्यात करने के कई अवसर हैं।

खासकर निर्माण सामग्री और हार्डवेयर उत्पादों की वहां काफी मांग है। उन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स से भारत टैक्स में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची भेजने को कहा। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा उन्हें दिए गए निमंत्रण के बाद उद्योग प्रदर्शनी में भाग लेने की उत्सुकता दिखाई।

